

सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन मजिल हमेशा शानदार मिलती है।



फाइनल में अखिर कौन किस पर पड़ेगा भारी? आंकड़ों के लिहाज से मिल रहे पैरियन के संकेत... >> पृष्ठ 7 पर

पंजाब में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए मान सरकार का बड़ा फैसला

अब एजेंसियों के बजाय सरकार करेगी सीधी नियुक्ति

65 हजार से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत

नौकरी में ठेकेदारी सिस्टम अब खत्म

आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल करने की तैयारी, विधानसभा में लाया जाएगा विधेयक (बिल)

>> प्रथम न्यूज | चंडीगढ़ 30 मई (एएम नाथ)

पंजाब में 65 हजार से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भगवंत मान सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। शनिवार को सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक में यह फैसला लिया गया है कि नौकरी में ठेकेदारी सिस्टम को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा और आगे से सीधे सरकार ही नौकरी देगी। पंजाब विधानसभा में इसके संबंध में बिल लाया जाएगा। इस फैसले से पंजाब



के 65 हजार से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी बड़ी राहत पाएंगे और लाभ हासिल करेंगे। सीएम मान ने बताया कि आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधे सरकार के कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया जाएगा। उनके बीच कोई एजेंसी या कोई ठेकेदार नहीं होगा।

2 कैटेगरी में सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे कर्मचारी

सीएम भगवंत मान ने प्रेस वार्ता करते



हुए विस्तार से इस संबंध में जानकारी दी है। सीएम मान ने बताया कि पंजाब के 51 सरकारी विभागों से संबन्धित 65,048

आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए यह एक ऐतिहासिक फैसला है और वो इस लाभ के दायरे में आएंगे। आउटसोर्स कर्मचारियों की 2 कैटेगरी रखी गई हैं। पहली गैर-जोखिम कैटेगरी और दूसरी जोखिम कैटेगरी।

सीएम मान ने कहा कि गैर-जोखिम कैटेगरी वाले वो आउटसोर्स कर्मचारी सीधे सरकार के कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होंगे, जिन्होंने 5 साल की सेवा पूरी कर ली है। उन कर्मचारियों को सीधे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट पर

लिया जाएगा। वहीं जोखिम भरे काम करने वाले कर्मचारियों को इस समयसीमा में छूट दी गई है। सीएम मान के अनुसार, जोखिम भरे काम करने वाले कर्मचारी 5 साल की बजाय सिर्फ 3 साल की सेवा पूरी कर लेने पर सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किए जाएंगे। सीएम ने जानकारी दी कि कैबिनेट से मंजूरी मिलने और ऑर्डिनेंस पास होने के बाद सरकार के इस फैसले से 26,400 कर्मचारियों को तुरंत फायदा मिलेगा। वे सीधे सरकार के अधीन आ जाएंगे।

बाक़ी को समय अनुसार सॉिनयोरिटी के हिसाब से आउटसोर्सिंग से हटाकर सरकार के कॉन्ट्रैक्ट पर लाया जाएगा। सीएम ने यह भी कहा कि सरकार के कॉन्ट्रैक्ट पर आने वाले आउटसोर्स कर्मचारी बाद में सरकार के नियम के हिसाब से रेगुलर भी होंगे।

सारी सरकारी सविधाएं और सहुलियतें मिलेंगी

सीएम भगवंत मान ने बताया कि सरकार के कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किए जाने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को भी सरकारी कर्मचारियों की तरह ही सारी सविधाएं और सहुलियतें मिलेंगी। उन्हें भी कैलेंडर अनुसार तय सरकारी छुट्टियां दी जाएंगी। कर्मचारियों को PF, ESI, ग्रैच्युटी समेत सभी कानूनी सुविधाएं दी जाएंगी। इसके साथ ही उन पर वो सारे सरकारी नियम लागू होंगे, जो सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं। किसी भी कर्मचारी को बिना लिखित कारण और सुनवाई का अवसर दिए नहीं हटाया जा सकेगा। मसलन मान सरकार का आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अब तक का यह सबसे बड़ा रोजगार और कर्मचारी कल्याण सुधार कदम है। वहीं सीएम मान ने जानकारी दी है कि पंजाब के कर्मचारियों और पेंशनर्स के एरियर और DA के मामलों को सुलझाने के लिए एक स्पेशल कैबिनेट सब-कमेटी भी बनाई गई है। इसके अलावा, भ्रष्टाचार के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए पंजाब में 7 नए स्पेशल कोर्ट बनाने की भी मंजूरी दी गई है। सीएम मान ने कहा कि आमतौर पर कर्मचारियों का हक मारने के दिन अब खत्म हो गए हैं। आपको सरकार पंजाब के हर वर्ग की भलाई और उनके सुन्दर भविष्य के लिए पूरी तरह से कमिटेड है।

नहीं हो सकेगा आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण

सीएम मान ने कहा कि नौकरी में ठेकेदारी सिस्टम को हमेशा के लिए खत्म करने की मंजूरी से आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण रुकेगा। अब कोई बिचौलिया या कॉन्ट्रैक्टर नहीं होगा, जो उनसे कमिशन ले पाये। उनसे ज्यादा सैलरी पर साइड करार कर कम सैलरी दे और काम ज्यादा कराये। सीएम ने कहा कि अब हर कर्मचारी को

सीधे सरकारी नौकरी देगी और कर्मचारियों की तय कमाई सीधे उनके बैंक अकाउंट में आएगी। कोई उनकी मेहनत की सैलरी पर डाका नहीं डाल पाएगा। सीएम ने बताया कि वह जब जन्मभारों में जाते थे तो बहुत से नौजवान युवक और युवतियां उनसे ठेकेदारी सिस्टम से उन्हें निकालने और सरकार के कॉन्ट्रैक्ट पर लाने की मांग करते थे।

संक्षिप्त न्यूज

15 साल की उम्र में रचा इतिहास

क्रिकेट सनसनी वैभव सूर्यवंशी बनेंगे झारखंड स्वास्थ्य विभाग के ब्रांड एंबेसडर

मंत्री डॉ. इरफान अंसारी का बड़ा ऐलान



रांची (ब्यूरो) - क्रिकेट जगत में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी, अद्भुत प्रतिभा और कम उम्र में ही पूरे देश को प्रभावित करने वाले युवा क्रिकेटर सितारे वैभव सूर्यवंशी को झारखंड का स्वास्थ्य विभाग सम्मानित करने के साथ-साथ विभाग का ब्रांड एंबेसडर भी बनाया। मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि भले ही वैभव की टीम मैच हार गई हो, लेकिन उन्होंने करोड़ों भारतीयों का दिल जीता है। इतनी कम उम्र में बड़े-बड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर के गेंदबाजों का जिस आत्मविश्वास और आक्रामकता से सामना करते हुए लगातार धुनाई करना, यह असाधारण प्रतिभा का प्रमाण है। वैभव ने केवल अपना नाम ही नहीं, बल्कि अपने माता-पिता, बिहार और पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। इसके लिए दिल से बधाई देते हुए मंत्री ने कहा है कि जल्द ही उन्हें झारखंड में सम्मानित किया जाएगा।

पाकिस्तान से लौट रहे अफगान शरणार्थियों से भरा ट्रक पलटा, 18 की मौत

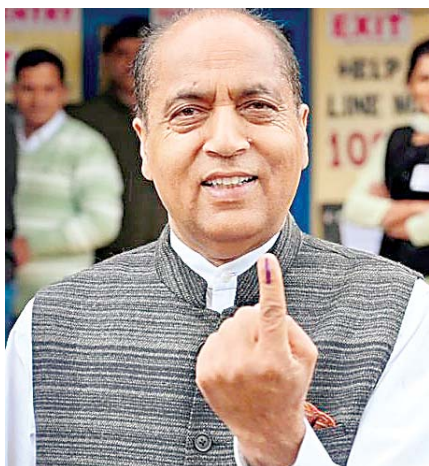
मृतकों में 10 बच्चे और 5 महिलाएं शामिल

काबुल (एजेंसी) - अफगानिस्तान के पूर्वी लघमान प्रांत में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। पाकिस्तान से लौट रहे अफगान शरणार्थियों को ले जा रहा एक ट्रक काबुल-नंगरहार मुख्य राजमार्ग पर पलटा गया। हादसे में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 35 अन्य घायल हो गए। मृतकों और घायलों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। प्रांतीय राज्यपाल के प्रवक्ता अब्दुल मलिक नियाजई के अनुसार, मृतकों में 10 बच्चे और 5 महिलाएं शामिल हैं।

हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों और बचाव दल ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और घायलों को नंगरहार के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। बताया जा रहा है कि ट्रक में सवार लोग उन हजारों अफगान शरणार्थियों में शामिल थे, जिन्हें हाल के महीनों में पाकिस्तान छोड़ना पड़ा है। पाकिस्तान ने 2023 से अवैध प्रवासियों के खिलाफ अभियान शुरू किया था, जिसके बाद बड़ी संख्या में अफगान नागरिकों को वापसी हुई। इसी दौरान ईरान ने भी अफगान प्रवासियों की वापसी की प्रक्रिया तेज कर दी थी। परिणामस्वरूप लाखों अफगान अपने देश लौट चुके हैं।

बारिश और तेज हवाओं के बीच पंचायत चुनाव में उमड़ा जनसैलाब, तीसरे चरण में 63.20% मतदान

खराब मौसम भी नहीं रोक सका लोकतंत्र का उत्साह, हिमाचल में पंचायत चुनाव के अंतिम चरण का मतदान संपन्न



>> प्रथम न्यूज | शिमला 30 मई (बी शर्मा)

हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों के तीसरे और अंतिम चरण के लिए शनिवार को हुए मतदान में मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बारिश और तेज हवाओं के बावजूद सुबह सात बजे से मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिलीं। इस चरण में प्रदेश की 1,189 ग्राम पंचायतों के लिए मतदान कराया गया, जिसमें 15 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र थे।

खराब मौसम के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला। कई बुजुर्ग मतदाताओं ने मतदान कर लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया। ग्राम पंचायत सलिलांचा के 102 वर्षीय चंदे राम, नालागढ़ विकास खंड की



घड़याच पंचायत के 100 वर्षीय दुर्गा राम, डोहाग के 78 वर्षीय चतर लाल और 86 वर्षीय शुकूर राम ने मतदान किया। वहीं कुल्लू जिले की हाट पंचायत में 90 वर्षीय देवकु देवी तथा सोलन की डुमैहर पंचायत में 88 वर्षीय रामस्वरूप पाल भी मतदान केंद्र पहुंचे। पंचायत चुनावों में मतदान मतपत्रों के माध्यम से कराया गया। किसी भी राजनीतिक दल के चुनाव चिह्न का उपयोग नहीं किया गया। विभिन्न पदों के लिए अलग-अलग रंगों के मतपत्र निर्धारित किए गए थे। वार्ड सदस्य के लिए सफेद, उपप्रधान के लिए पीला, प्रधान के लिए हरा, पंचायत समिति सदस्य के लिए गुलाबी तथा जिला परिषद सदस्य के लिए नीले रंग के मतपत्र का प्रयोग किया गया।

शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा

बल तैनात किए गए थे। हालांकि हमीरपुर जिले के ऊहल जिला परिषद वार्ड के बनालग मतदान केंद्र में विधायक के पहुंचने को लेकर विवाद हो गया, जिससे कुछ समय के लिए दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई। तीसरे चरण में कुल 63.20 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। 15,39,161 पंजीकृत मतदाताओं में से 9,70,391 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान प्रतिशत के लिहाज से सिरमौर जिला 71.88 प्रतिशत मतदान के साथ प्रदेश में सबसे आगे रहा।

इसके अलावा सोलन में 66.23, शिमला में 65.72, उना में 64 तथा किन्नौर में 63.64 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। कांगड़ा जिले में तीन बजे तक 70.05 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव परिणाम 31 मई को घोषित किए जाएंगे।

कुरुक्षेत्र को मिली बड़ी सौगात

28 किमी बाईपास परियोजना को केंद्र की मंजूरी

>> प्रथम न्यूज | चंडीगढ़ 30 मई (पुनीत महाजन)

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के लिए प्रस्तावित 28 किलोमीटर लंबे बाईपास परियोजना को केंद्र सरकार की बड़ी सौगात बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना से कुरुक्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी और लंबे समय से यातायात जाम की समस्या से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत प्राप्त होगी।

मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रस्तावित बाईपास ज्योतिषर के निकट इंदबरी से शुरू होकर एसएच-6, एमडीआर-119, किरमच रोड, अमीन रोड और एनएच-44 को जोड़ते हुए मथाना तक जाएगा। यह मार्ग क्षेत्र को सड़क संपर्क व्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ-साथ यातायात को सुगम बनाते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

उन्होंने कहा कि परियोजना के पूरा होने के बाद पिपली क्षेत्र में ट्रैफिक का दबाव काफी हद तक कम हो जाएगा। इससे शहर में लगने वाले जाम से स्थानीय रहनेवाले की उम्मीद है। स्थानीय नागरिकों के अलावा कुरुक्षेत्र आने-जाने वाले हजारों



यात्रियों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि नया बाईपास दिल्ली-यमुनानगर-हरिद्वार मार्ग पर यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाएगा। साथ ही पंजाब और कैथल की ओर जाने वाले वाहनों को भी बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। परियोजना के क्रियान्वयन से यात्रा समय में कमी आएगी, ईंधन की बचत होगी और सड़क परिवहन व्यवस्था अधिक प्रभावी बनेगी।

राज्य सरकार का मानना है कि यह बाईपास परियोजना केवल यातायात सुधार तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को गति देने और नए निवेश को आकर्षित करने में भी अहम भूमिका निभाएगी। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और कुरुक्षेत्र के समग्र विकास को नई रफ्तार मिलेगी।

चंबा में दर्दनाक हादसा: खाई में गिरी कार, दो बच्चों समेत आठ पर्यटकों की मौत

सच दर्रा मार्ग पर बड़ा हादसा, खाई में समाई पर्यटकों की कार, बचाव अभियान जारी, हिमाचल में पर्यटन यात्रा बनी त्रासदी

>> प्रथम न्यूज | चंबा 30 मई (एएम नाथ)

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो बच्चों समेत आठ पर्यटकों की मौत हो गई है। यह दुर्घटना चुराह उपमंडल के बैरागढ़-सच दर्रा-किलाड मार्ग पर हुई, जब पर्यटकों को लेकर जा रही एक कार करीब 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे की जानकारी स्थानीय लोगों को शनिवार दोपहर में मिली, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस ने राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। अधिकारियों के अनुसार, कार हिमाचल के सबसे दुर्गम और चुनौतीपूर्ण मार्गों में गिने जाने वाले बर्फ से ढके सच दर्रे की ओर जा रही थी। वाहन में बंगलूरू और कोलकाता से आए पर्यटक,

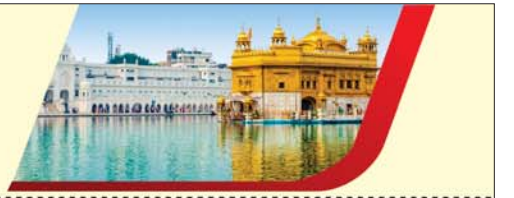


दो बच्चे तथा टैक्सि चालक सवार थे। सभी पर्यटक डलहौजी घूमने आए थे और बर्फबारी तथा पहाड़ी क्षेत्रों का आनंद लेने के लिए सच दर्रा क्षेत्र की ओर निकले थे। निर्धारित समय पर वाहन के वापस नहीं लौटने पर टैक्सि मालिक को चिंता हुई। उसने जीपीएस के माध्यम से वाहन की लोकेशन जानी, जो कालावन क्षेत्र के पास एक ही स्थान पर स्थिर दिखाई दे रही थी। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से खोजबीन शुरू की गई। जांच के दौरान आशंका सही साबित हुई और वाहन गहरी खाई में दुर्घटनाग्रस्त मिला। चुराह के विधायक डा. हंस राज ने बताया कि खड़ी ढलान, दुर्गम भूभाग और खराब मौसम के कारण शवों को बाहर निकालने में भारी कठिनाई आ रही है। क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क भी उपलब्ध नहीं है, जिससे बचाव कार्य

प्रभावित हुआ। प्रशासन, पुलिस और स्थानीय टीमों की मदद से राहत अभियान जारी है। अधिकारियों ने बताया कि मौसम अनुकूल होने पर अभियान को और तेज किया जाएगा। हादसे से क्षेत्र में शोक की लहर है।

मृतक पर्यटकों की सूची

- 1 चालक विश्वास निवासी बनीखेत
- 2 अर्धदि चंद्रकांत निवासी (पलैट संख्या-001) काटगढ़ी बंगलूरू
- 3 प्राची पत्नी अर्चिद चंद्रकांत
- 4 बेता दर्श आयु 8 साल
- 5 अथाद आयु 11 साल
- 6 पीजी कार्टिकियन निवासी व्हाइट फ्रील्ड कर्नल डिप्टिन
- 7 मणिमाला पत्नी पीजी कार्टिकियन
- 8 नंदन पुत्र पीजी कार्टिकियन



संक्षिप्त न्यूज

शिवानी भगत को मिट्टू मदान ने सौंपा नियुक्ति पत्र



अमृतसर (साहिब दयाल) अमृतसर में कांग्रेस पार्टी में नव नियुक्त सदस्यों को नियुक्ति पत्र शहरी प्रधान मिट्टू मदान ने अपने ऑफिस में दिए। इस अवसर पर वेरका क्षेत्र से शिवानी भगत को जिला कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेट्री बनाए जाने पर नियुक्ति पत्र सौंपा। मिट्टू मदान ने कहा कि पार्टी में अहम स्थान और नियुक्ति पत्र मिलने से वर्कर्स के हौंसले और बढ़ेंगे। जो आने वाले समय में पार्टी की मजबूती के लिए काम तेजी से कर पाएंगे। इस मौके पर शिवानी भगत ने सौरभ मदान मिट्टू के साथ पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा बडिंज और कांग्रेस हाईकमान का विशेष धन्यवाद करते हुए कहा कि वे पार्टी द्वारा दी गई जिम्मेदारी को पूरी मेहनत से निभाएंगी। उन्होंने एमपी गुरजीत सिंह ओजला और पूर्व विधायक सुनील दत्ता का भी आभार प्रकट किया।

गुरदासपुर पुलिस ने 14 ग्राम हेरोइन के साथ दो नशा तस्करो को दबोचा



गुरदासपुर (संदीप सन्नो) - जिला पुलिस ने अलग-अलग क्षेत्रों से दो नशा तस्करो को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से कुल 14 ग्राम हेरोइन बरामद करने में सफलता हासिल की है। पहली कार्रवाई थाना सिटी गुरदासपुर की पुलिस द्वारा अमल में लाई गई। पुलिस ने दीपक कुमार उर्फ दीपू को गिरफ्तार कर उसके पास से 08 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इसी प्रकार, एक अन्य कार्रवाई में थाना काहनवान की पुलिस ने हैप्पी नाम के युवक को दबोचा है और उसके कब्जे से 06 ग्राम हेरोइन बरामद कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

नगर परिषद चुनाव जीतने वाले धर्मपाल चुघ ने मतदाताओं और समर्थकों को धन्यवाद दिया

जौरा, 30 मई (अंग्रेज बराड़) - आम आदमी पार्टी की ओर से जौरा नगर परिषद के वार्ड संख्या 8 से चुनाव जीतने वाले श्री धर्मपाल चुघ ने अपने मतदाताओं और समर्थकों को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए धर्मपाल चुघ ने कहा कि वार्ड निवासियों ने उन्हें पूरा समर्थन दिया है, जिसके लिए वे हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। उन्होंने जौरा नगर परिषद के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन की भी प्रशंसा की। धर्मपाल चुघ ने यह भी कहा कि वे अपने वार्ड निवासियों और शहरवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। उन्होंने कहा कि वे विधायक श्री नरेश कटारिया के नेतृत्व में जौरा शहर को विकास के मामले में एक आदर्श शहर बनाने के लिए तत्पर हैं। अंत में, धर्मपाल चुघ ने कहा कि वे अतीत में जौरा निवासियों की सेवा में रहे हैं और दिन-रात जौरा के लोगों के बीच उपस्थित रहेंगे।

शिरोगणि अकाली दल के शहरी अध्यक्ष सुखदेव बिट्टू विज ने मतदाताओं और समर्थकों का धन्यवाद किया

जौरा, 30 मई (अंग्रेज बराड़) - जौरा नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष और प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता सुखदेव बिट्टू विज ने शिरोगणि अकाली दल की ओर से जौरा नगर परिषद के वार्ड संख्या 12 से चुनाव लड़ा और अपने मतदाताओं एवं समर्थकों को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर सुखदेव बिट्टू विज ने कहा कि वार्ड निवासियों ने उन्हें पूरा समर्थन दिया है, जिसके लिए वे सदा उनके ऋणी रहेंगे। वार्ड निवासी 10x वर्षीय हरनाम सिंह का आशीर्वाद लेकर सुखदेव बिट्टू विज ने उन्हें विशेष धन्यवाद दिया। उन्होंने जौरा नगर परिषद के शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पुलिस प्रशासन की भी सराहना की। सुखदेव बिट्टू विज ने यह भी कहा कि ईश्वर की कृपा से वे जनता के विश्वास को खिले उतरेंगे।

पंजाब एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी को तैयार : मान

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तैयारियों की समीक्षा की, विशेषज्ञों की समिति बनाने के निर्देश

» प्रथम न्यूज | चंडीगढ़
30 मई (एएम नाथ)

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब इस वर्ष के अंत में होने वाली हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि टूर्नामेंट से जुड़े सभी बुनियादी ढांचा और प्रबंधकीय कार्य सितंबर से पहले हर हाल में पूरे किए जाएं, ताकि आयोजन को सफल बनाने में कोई कमी न रहे। उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता की सफलता सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों, खिलाड़ियों और अन्य भागीदारों को शामिल करते हुए एक प्रबंधकीय समिति गठित की जाए। यह समिति सभी तैयारियों को नियमित समीक्षा करेगी और समयबद्ध तरीके से कार्यों को पूरा करवाएगी। इसके साथ ही जालंधर और मोहाली में चल रहे विकास कार्यों की निगरानी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को एक उच्च-शक्ति समिति के गठन को



भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जालंधर और मोहाली के स्टेडियमों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाए। उन्होंने भरसा दिलाया कि राज्य सरकार भारतीय हॉकी प्रशासन को हर संभव सहयोग प्रदान करेगी और इस ऐतिहासिक आयोजन को सफलता

के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब की धरती ने देश को अनेक महान हॉकी खिलाड़ी दिए हैं और ऐसे अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट की मेजबानी से राज्य के युवाओं को खेलों से जुड़ने की नई प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों, अधिकारियों और दर्शकों के लिए सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स तथा अन्य सुविधाओं के व्यापक प्रबंध किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में एशिया की छह शीर्ष हॉकी टीमों भाग लेंगी। पहली बार पंजाब को इस स्तर के अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी का अवसर मिला है, जो राज्य के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन पंजाब में खेल संस्कृति को मजबूत करेगा और राज्य की खेलों में पुरानी पहचान को पुनर्स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बैठक में मुख्य सचिव के.पी. सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव डॉ. रावी भगत, नितिन कोहली सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सीलबंद लिफाफे का खुलासा : कर्मचारियों ने पंजाब सरकार पर हाईकोर्ट को गुमराह करने का लगाया आरोप, संघर्ष का किया ऐलान

» प्रथम न्यूज | जालंधर
30 मई (कुलदीप सिंह)

पंजाब सरकार द्वारा गठित कैबिनेट उप-समिति द्वारा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की मांगों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय को दिया गया सीलबंद लिफाफा अब सार्वजनिक हो गया है। इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए पंजाब कर्मचारी एवं पेंशनभोगी संयुक्त मोर्चा के संयोजक सतीश राणा, रणजीत सिंह रनवा, करम सिंह धनोआ, धनवंत सिंह भट्टल, भजन सिंह गिल, कुलविंदर सिंह ढिल्लों, गानदीप सिंह भुल्लर, जयनजीत सिंह, मनजीत सिंह बसारे, सुखदेव सिंह सैनी, बाज सिंह खैरा, कुलदीप सिंह, जगदीश सिंह चहल, जसवीर सिंह तलवारा, राधे शाम, सुरजीत सिंह गगरा, बोबिंदर सिंह, करमजीत सिंह बिहला और दिग्विजय पाल शर्मा ने कहा कि सीलबंद लिफाफे के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में गलत तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत करके कैबिनेट उप-समिति ने एक बार फिर खुद को कटघरे में खड़ा कर लिया है, जबकि कैबिनेट उप-समिति ने माननीय न्यायालय को गुमराह करने का शर्मनाक और निंदनीय प्रयास किया है।

नेताओं ने कहा कि यदि मंत्रिमंडल की उप-समिति को तथ्य प्रस्तुत करने थे, तो उन्हें पंजाब के पृथक वेतन आयोग की पृष्ठभूमि और पंजाब के कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में किन कारकों



को आधार माना जाता है, इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए था। नेताओं ने कहा कि 15 पृष्ठों की सीलबंद रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय, उन्हें इस पूरी श्रेणी की तुलना उन राज्यों से भी करनी चाहिए थी जो पंजाब से अधिक वेतनमान दे रहे हैं। उन्होंने उन राज्यों के बारे में भी बात की जो अपने कर्मचारियों को 58 और 60वें महंगाई भत्ता दे रहे हैं, जो हर पांच साल में वेतन आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, जो वृद्धावस्था पेंशन दे रहे हैं, जो विभिन्न प्रकार के भत्ते दे रहे हैं, जिन राज्यों में कर्मचारियों का तीन साल को परिवीक्षा

अवधि के दौरान शोषण नहीं हो रहा है, और जो राज्य केंद्रीय वेतनमान नहीं दे रहे हैं। इसके साथ ही, उन्हें आशा कार्यकर्ताओं, मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले भत्ते की तुलना भी करनी चाहिए थी और यह बताया चाहिए था कि कौन से राज्य पंजाब से अधिक भत्ता दे रहे हैं। उन्हें यह भी बताया चाहिए था कि हमारे राज्य में 20-25 वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी करने की क्या नीति है। इसके अलावा, उन्हें यह भी बताया चाहिए था कि कौन से अन्य राज्य 200 रुपये का कर

नहीं वसूल रहे हैं। इस समिति को यह भी बताया चाहिए था कि हमारे विधायक और मंत्री किस राज्य से अधिक वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं और अन्य राज्यों की तुलना में हमारे विभिन्न प्रकार के फिजुलखर्चों, वाहनों, विशेष रूप से मुफ्त विज्ञापनों पर कितना पैसा खर्च हो रहा है। इसके अलावा, इसे यह भी बताया चाहिए था कि सरकारी खजाने की लूट कैसे हो रही है और हमारे राज्य में किन राज्यों में मादक पदार्थों की तस्करी, खनन गुंडगर्दी और हत्याएं अधिक हो रही हैं। इसके अलावा, यदि पंजाब सरकार

में थोड़ी भी नैतिकता होती, तो उसे यह भी बताना चाहिए था कि हमारे विधायकों और मंत्रियों के पास वर्तमान में कितनी संपत्ति है और विधायक/मंत्री बनने से पहले उनके पास कितनी संपत्ति थी।

संयुक्त मोर्चे के उपरोक्त नेताओं ने कहा कि कैबिनेट उप-समिति की यह झूठी और तथ्यात्मक रिपोर्ट कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को डराने-धमकाने का एक घिनौना प्रयास मात्र है, जिसे पंजाब के 7 लाख कर्मचारी और पेंशनभोगी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। नेताओं ने कहा कि संयुक्त मोर्चे द्वारा तैयार कार्यक्रम के तहत, 30 जून तक जिला सम्मेलन आयोजित करके कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आले संघर्ष के लिए तैयार किया जाएगा, जिसके तहत पंजाब सरकार के चरणों में आग लगाने के लिए जुलाई और अगस्त महीनों में पंजाब सरकार के मंत्रियों और विधायकों के आलीशान घरों के सामने व्यापक प्रदर्शन किए जाएंगे। इसके बाद, सितंबर में क्षेत्रीय रैलियां आयोजित की जाएंगी और अक्टूबर में सरकारी की जड़ों को उखाड़ने के लिए पंजाब स्तर पर एक अभूतपूर्व और बड़ी राज्य स्तरीय रैली आयोजित की जाएगी। उपरोक्त नेताओं ने यह भी चेतावनी दी कि आगामी विधानसभा चुनावों से पहले और उसके दौरान, इस सरकार की कुप्रथाओं और जनता से किए गए झूठे वादों के खिलाफ इसी तरह का अभियान चलाया जाएगा।

डॉ. भीम राव अंबेडकर जी ने देश के हर वर्ग को बराबर के हक देकर भारत की नींव रखी : संत सर्वण दास, संत सतविंदर हीरा

» प्रथम न्यूज | होशियारपुर
30 मई (तरसेम दीवाना)

आदि धर्म साधु समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत सर्वण दास गद्दी नशीन सलेमटाबरी लुधियाना और अलॉ इंडिया आदि धर्म मिशन भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत सतविंदर हीरा ने रहरबर-ए-कौम, भारतीय संविधान के निर्माता और नारी मुक्तिदाता बाबा साहेब डॉ. भीम राव अंबेडकर जी के महान जीवन और उनके ऐतिहासिक योगदान को सलाम करते हुए कहा कि बाबा साहेब डॉ. बी. आर. अंबेडकर सिर्फ किसी एक वर्ग के नेता नहीं थे, बल्कि वे समूची मानवता के रहरबर थे, जिन्होंने भारत में बसते हर धर्म, जाति और वर्ग के लोगों के लिए बराबर के हक सुनिश्चित किए। जिस कारण आज भारत का हर नागरिक आजादी, समानता और सम्मान की जिंदगी जी रहा है, तो इसका पूरा श्रेय बाबा साहेब द्वारा लिखे पवित्र संविधान को जाता है। उन्होंने विशेष तौर पर जिक्र किया कि बाबा साहेब ने भारतीय नारी को सदियों की गुलामी और कुरीतियों की जंजीरों से मुक्त करवाया। हिंदू कोड बिल के माध्यम से उन्होंने महिलाओं को



वे बाबा साहेब के बताए हुए मार्ग पढ़ें, जुड़ें और संघर्ष करो पर चलें। उन्होंने कहा कि संविधान और इसमें मिले अधिकारों की रक्षा करना हमारा सबका परम कर्तव्य है।

शिक्षा, संपत्ति में हिस्सा और वोट डालने जैसे ऐतिहासिक अधिकार देकर पुरुषों के बराबर खड़ा किया। आज अगर हमारी बेटियां हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रही हैं, तो वह बाबा साहेब की ही बहादुरी है! उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने संविधान में ऐसी धाराएं शामिल कीं, जिससे दल-कुचले, पिछड़े, मजदूरों, किसानों और कर्मचारियों सहित हर वर्ग के हितों की रक्षा हुई। उन्होंने देश में %एक वोट, एक मूल्य% का सिद्धांत लागू करके लोकतंत्र की असली परिभाषा तय की! उन्होंने समूह संगत और देशवासियों से अपील की कि वे बाबा साहेब के बताए हुए मार्ग पढ़ें, जुड़ें और संघर्ष करो पर चलें। उन्होंने कहा कि संविधान और इसमें मिले अधिकारों की रक्षा करना हमारा सबका परम कर्तव्य है।

दंतचिकित्सा पर कार्यशाला का आयोजन किया गया

» प्रथम न्यूज | जौरा
30 मई (अंग्रेज बराड़)

अकाल कॉलेज परिषद के सचिव श्री जसवंत सिंह खैरा के मार्गदर्शन में, अकाल समूह के संस्थान विद्यार्थियों के कल्याण के लिए पूरे उत्साह से काम कर रहे हैं। विद्यार्थियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य जागरूकता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, अकाल अकादमी के प्रधानाचार्य डॉ. विजय पलाहा और सभी कर्मचारियों के सहयोग से, संत अतर सिंह अकाल अकादमी मस्तुआना साहिब ने अकादमी परिसर में घायल दांतों के आपातकालीन प्रबंधन विषय पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का आयोजन पीजीआईएमईआर गबड़ू की विशेषज्ञ डॉ. अमनदीप कौर और उनकी टीम ने प्रबंधन के सहयोग से किया। चिकित्सा टीम ने विशेष रूप से शिक्षकों, खेल प्रशिक्षकों और विद्यालय के कर्मचारियों को बहुत ही सरल भाषा में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की।



इस सत्र के दौरान, कर्मचारियों को खेल के मैदान में या स्कूल के समय के दौरान बच्चों के दांतों में किसी भी प्रकार की चोट या आघात के तत्काल प्रबंधन, प्राथमिक उपचार (बुनियादी उपचार) और सुरक्षा नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अभियान के बारे में बात करते हुए, प्रधानाचार्य श्री विजय पलाहा ने कहा, छात्रों की सुरक्षा केवल सामान्य देखभाल तक सीमित नहीं है। खेल के मैदान में दुर्घटनाएं अचानक हो सकती हैं और शुरुआती कुछ मिनटों में दंत आपात स्थिति का सही ढंग से इलाज करने से बच्चे के अनमोल दांत को हमेशा के लिए बचाया जा सकता है। सत्र के अंत में एक विशेष प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षकों और खेल प्रशिक्षकों ने चिकित्सा दल के साथ बच्चों की प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित अपने संदेह साझा किए और विशेषज्ञों द्वारा उन्हें संतोषजनक उत्तर दिए गए। इस अवसर पर अकादमी के सभी शिक्षक, खेल विभाग के प्रशिक्षक और चिकित्सा कक्ष के प्रभारी विशेष रूप से उपस्थित थे।

सीनियर सेकेंडरी स्कूल मगरमूदियां में नशे के विरुद्ध जागरूकता कैंप का आयोजन

» प्रथम न्यूज | जालंधर
30 मई (कुलदीप सिंह)

नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत विद्यार्थियों को नशे के जानलेवा दुष्प्रभावों और समाज में इसकी बढ़ती चिंताजनक स्थिति के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया। यह जागरूकता कैंप रेड क्रॉस इंटीग्रेटेड रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्ट्स, गुरदासपुर द्वारा सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गांव मगरमूदियां में प्रिंसिपल हरविंदर कौर की अध्यक्षता में लगाया गया। विद्यार्थियों को शारीरिक और मानसिक नुकसान के प्रति संवेदनशील बनाना मुख्य लक्ष्य



व सचेत करना था, ताकि वे समय रहते इस सामाजिक बुराई के प्रति जागरूक हो सकें। नशा एक जटिल बीमारी, लेकिन सही इलाज और काउंसलिंग से सुधार संभव कैंप के दौरान आई.आर.सी.ए. गुरदासपुर की विशेषज्ञ टीम के सदस्यों ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए जानवर्धक व्याख्यान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि नशा एक बेहद जटिल बीमारी है, लेकिन परिवार और समाज के निरंतर सहयोग, उचित चिकित्सीय इलाज और मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग (सलाह) के जरिए इससे पूरी तरह छुटकारा पाया जा सकता है। टीम ने नशे के आदी हो रहे व्यक्तियों के शुरुआती लक्षणों को पहचानने, समय पर हस्तक्षेप करने और सहायता प्रणालियों की भूमिका पर विशेष

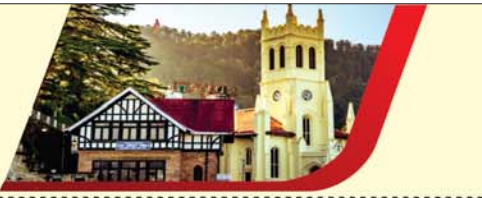
मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग (सलाह) के जरिए इससे पूरी तरह छुटकारा पाया जा सकता है। टीम ने नशे के आदी हो रहे व्यक्तियों के शुरुआती लक्षणों को पहचानने, समय पर हस्तक्षेप करने और सहायता प्रणालियों की भूमिका पर विशेष

रूप से प्रकाश डाला। युवा पीढ़ी की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य पर जोर विशेषज्ञों ने देश की युवा पीढ़ी को नशे के इस गंभीर खतरे से बचाने की सख्त जरूरत पर बल दिया। उन्होंने विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर नशे के पड़ने वाले घातक प्रभावों की चर्चा की और उन्हें जीवन में सही व सकारात्मक फैसले लेने के लिए मार्गदर्शन किया। उन्होंने छात्र-छात्राओं को नशे जैसी बुराइयों से दूर रहकर अपने जीवन में कड़ी मेहनत करने और देश-दुनिया में सफलता हासिल करने के लिए प्रेरित किया। इस बेहद उपयोगी और प्रेरणादायक जागरूकता सेशन का समापन एक गरिमामयी शपथ ग्रहण समारोह के साथ हुआ, जिसमें उपस्थित सभी विद्यार्थियों और स्टाफ सदस्यों ने नशे को नशों से दूर रखने और समाज को नशा मुक्त बनाने में अपना योगदान देने का संकल्प लिया।

RTI एक्टिविस्ट सिमरनजीत सिंह मर्डर केस में बड़ा खुलासा, चचेरा भाई गिरफ्तार

जालंधर (डोगरा) - शहर के चर्चित RTI एक्टिविस्ट सिमरनजीत सिंह हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए उनके चचेरे भाई शरणजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि हत्या के पीछे पारिवारिक प्रॉपर्टी विवाद मुख्य कारण था। पुलिस अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि जांच में पता चला है कि सिमरनजीत सिंह को मार के पीछे गोली मारी गई थी, जो आरपार होकर माथे से बाहर निकल गई। वारदात के समय सिमरनजीत से मिलने उनके कुछ रिश्तेदार आए हुए थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और उन पर गोली चला दी गई। गोली लगने से सिमरनजीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आरोपी वारदात के बाद फरार हो गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू की और आरोपी शरणजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि वारदात में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया गया है, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। मामले में आगे की जांच जारी है और पुलिस अन्य पहलुओं को भी खंगाल रही है।





संक्षिप्त न्यूज

इतिहास और अर्थशास्त्र के शिक्षकों की मर्ती परीक्षा 28 जून को

हमीरपुर (ब्यूरो) - हिमाचल प्रदेश चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने पोस्ट कोड-26025 के तहत इतिहास के शिक्षकों और पोस्ट कोड-26030 के तहत अर्थशास्त्र के शिक्षकों की मर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) की तिथि घोषित कर दी है।

आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि इन दोनों श्रेणियों के पदों की परीक्षा 28 जून को होगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा से एक सप्ताह पहले आयोग की वेबसाइट एचपीआरसीए.एचपी.जीओवी.इन hpcca.hp.gov.in पर एक लिंक का प्रावधान किया जाएगा, जिससे अभ्यर्थी अपना रोल नंबर एवं एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। रोल नंबर और परीक्षा केंद्र की जानकारी मोबाइल फोन पर एसएमएस के माध्यम से भी भेजी जाएगी।

सचिव ने सभी अभ्यर्थियों से नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट पर या अपने मोबाइल पर एसएमएस और ईमेल पर ताजा स्टेटस चेक करते रहने की अपील की है। अधिक जानकारी के लिए आयोग के कार्यालय में या दूरभाष नंबर 01972-222204 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी राजेश कुमार कौशल हुए सेवानिवृत्त, 38 वर्षों की सेवाओं का गौरवपूर्ण सफर हुआ पूर्ण



बिलासपुर, (जितेंद्र गौतम) - हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग में लगाभ 38 वर्षों तक समर्पित एवं उत्कृष्ट सेवाएं देने के उपरांत क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी राजेश कुमार कौशल आज 30 मई, 2026 को सेवानिवृत्त हो गए हैं।

नवंबर 1988 में परिवहन विभाग में अपनी सेवाएं आरंभ करने वाले राजेश कुमार कौशल ने अपने लंबे सेवाकाल के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। अपने सेवाकाल में उन्होंने परिवहन संबंधी सेवाओं की अधिक प्रभावी एवं जम्नोमुख बनाने के लिए उल्लेखनीय कार्य किए।

उनकी कार्यनिष्ठा, सरल व्यवहार और कर्तव्यपरायणता के कारण वह विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों तथा आमजन के बीच विशेष पहचान रखते हैं। सेवानिवृत्ति के अवसर पर विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों, मित्रों एवं शुभचिंतकों ने उनके दीर्घ, सफल एवं प्रेरणादायी सेवाकाल की सराहना करते हुए उनके स्वस्थ, सुखद एवं समृद्ध भविष्य की कामना की है। राजेश कुमार कौशल को सेवाएं परिवहन विभाग के लिए सदैव प्रेरणास्रोत बनी रहेंगी।

एक से 14 अगस्त तक धर्मशाला में होगी अग्निवीर मर्ती रैली : मर्ती निदेशक

धर्मशाला (ब्यूरो) - हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए अग्निवीर (सेना) मर्ती रैली का आयोजन 1 अगस्त से 14 अगस्त 2026 तक धर्मशाला में किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए मर्ती निदेशक कर्नल विशाल शाह ने बताया कि मर्ती रैली के दौरान हजारों अभ्यर्थियों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासनिक एवं आधारभूत व्यवस्थाओं को लेकर व्यापक तैयारियां की जाएंगी।

इसके लिए एसडीएम, खेल विभाग, पुलिस, स्वास्थ्य, नगर निगम, लोक निर्माण, विद्युत, जल शक्ति, दूरसंचार, शिक्षा सहित विभिन्न विभागों का सहयोग लिया जाएगा। मर्ती रैली के दौरान अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे सहित पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

नगर परिषद चंबा के नवनिर्वाचित सदस्यों को 3 जून को दिलाई जाएगी शपथ : उपमंडल अधिकारी प्रियांशु खाती

चंबा (एएम नाथ) - उपमंडल अधिकारी (नागरिक) चंबा प्रियांशु खाती ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश नगर परिषद निर्वाचन नियम, 2015 के नियम 88 के अंतर्गत नगर परिषद चंबा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने के कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

उन्होंने बताया कि नगर परिषद चंबा के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा एवं श्रद्धा की शपथ दिलाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण कार्यक्रम 03 जून को प्रातः 11:00 बजे उपमंडल अधिकारी (नागरिक) चंबा के कार्यालय कक्ष में आयोजित किया जाएगा।

विकास खंड नालागढ़ में पंचायती राज संस्थाओं के तीनों चरणों के चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न

नवाचन अधिकारी पंचायत एवं उपमंडलाधिकारी नालागढ़ नरेंद्र आहलूवालिया ने जानकारी देते हुए कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप विकास खंड नालागढ़ में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के प्रथम, द्वितीय और 30 मई 2026 को तृतीय एवं अंतिम चरण की मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण, निष्पक्ष तथा सफलतापूर्वक संपन्न हुई।

उन्होंने कहा कि तीनों चरणों के दौरान मतदाताओं ने लोकतंत्र के इस महापर्व में बड़े-चढ़कर भाग लिया।

उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान कहीं भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना अथवा कानून-व्यवस्था संबंधी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई, जो क्षेत्रवासियों की लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति गहरी निष्ठा को दर्शाती है।

उन्होंने कहा कि नरेंद्र आहलूवालिया ने कहा कि तृतीय चरण के अंतर्गत 26 ग्राम पंचायतों के लिए स्थापित 172 मतदान केंद्रों में मतदान प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न करवाई गई। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा तथा चुनाव प्रक्रिया के सुचारु संचालन के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए गए थे। उन्होंने कहा कि तृतीय चरण में निर्धारित 26 ग्राम पंचायतों के लिए कुल 38,773

प्रथम न्यूज | नालागढ़
30 मई (गुरजीत सिंह)



मतदाता थे। इनमें से 16,985 पुरुष तथा 16,744 महिला मतदाताओं ने अपने मतदाधिकार का प्रयोग किया। इस प्रकार कुल मतदान प्रतिशत 86.99 दर्ज किया गया। पुरुष मतदाताओं का मतदान प्रतिशत 85.87 तथा महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत 88.47 रहा। महिलाओं की उल्लेखनीय भागीदारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति उनकी जागरूकता, विश्वास एवं सक्रिय सहभागिता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों के तीनों चरणों को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने में प्रशासन, पुलिस विभाग, विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, चुनाव द्यूटी में तैनात कार्मिकों तथा मतदाताओं का सराहनीय सहयोग प्राप्त हुआ। सभी के समन्वित प्रयासों से चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाया जा सका। निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि तृतीय चरण में हुए प्रधान, उपप्रधान एवं वार्ड सदस्य पदों के परिणाम 30 मई, 2026 को ही घोषित किए वहाँ पंचायत समिति सदस्य तथा जिला परिषद सदस्य की मतगणना 31 मई, 2026 को राजकीय महाविद्यालय नालागढ़ में प्रातः 8:00 बजे से शुरू की जाएगी, जिसके उपरांत परिणाम घोषित किए जाएंगे।

हिमाचल प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला

चतुर्थ श्रेणी पेंशनरों को मिलेगा बकाया एरियर का पूरा भुगतान

प्रथम न्यूज | शिमला
30 मई (बी शर्मा)

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और उनके परिवारों को बड़ी राहत देते हुए वर्ष 2016 के बाद के पेंशन व फेमिली पेंशन एरियर का पूरा बकाया जारी करने का निर्णय लिया है। वित्त विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार अब पात्र पेंशनरों और परिवार पेंशनरों के लंबित एरियर का भुगतान तत्काल प्रभाव से किया जाएगा। इस फैसले से हजारों

पेंशनरों और उनके आश्रितों को सीधा लाभ मिलेगा। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए अथवा सेवा के दौरान निधन होने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पेंशन एवं फेमिली पेंशन एरियर का शेष भुगतान तुरंत किया जाएगा। इसके साथ ही उन पोस्ट-2016 पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को भी राहत दी गई है जिनकी मूल पेंशन 25 हजार रुपये तक तथा फेमिली पेंशन 15 हजार रुपये प्रतिमाह तक है।



वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस भुगतान के बाद संबंधित पात्र पेंशनरों का लंबित एरियर शून्य हो जाएगा। लंबे समय से एरियर भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए यह निर्णय बड़ी राहत वाला माना जा रहा है। पूर्व में दी गई अंतरिम राहत और महंगाई राहत की किशतों को कुल एरियर राशि में समायोजित किया जाएगा। ऐसे में शुद्ध (नेट) राशि का ही भुगतान संबंधित पेंशनरों को मिलेगा। यदि किसी मामले में पूर्व में दी गई राहत

राशि अधिक निकलती है, तो शेष समायोजन भविष्य में मिलने वाले एरियर या महंगाई राहत से किया जाएगा।

विभाग ने सभी पेंशन वितरण प्राधिकरणों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निर्देश दिए हैं कि अतिरिक्त भुगतान की स्थिति में समायोजन सुनिश्चित करते हुए केवल वास्तविक देय राशि ही जारी की जाए। सरकार के इस निर्णय को आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के पेंशनरों के लिए राहतभरा कदम माना जा रहा है।



30 मई को हुए मतदान के तीसरे चरण में ग्राम पंचायत ढांग नहिली, डाकघर प्लासी कलां के वार्ड नंबर 4 की निर्वासी ममता रानी ने पहली बार अपने मतदाधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने उत्साहपूर्वक मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भागीदारी निभाई और अन्य मतदाताओं को भी मतदान के लिए प्रेरित किया। -गुरजीत सिंह

नगर निकाय और पंचायती राज चुनावों को हाईजैक करने का प्रयास कर रही कांग्रेस सरकार : डॉ. राजीव बिंदल

जनता के जनादेश को धनबल, सत्ताबल और नियमों में बदलाव के जरिए पलटने की साजिश : भाजपा

प्रथम न्यूज | शिमला
30 मई (बी शर्मा)

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर नगर निकाय और पंचायती राज चुनावों को हाईजैक करने का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार लगातार लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं, संवैधानिक मूल्यों और स्थापित परंपराओं को कमजोर करने का कार्य कर रही है।

डॉ. बिंदल ने कहा कि जिन पंचायती राज चुनावों का आयोजन अक्टूबर-नवंबर 2025 में होना चाहिए था, उन्हें जानबूझकर टालकर प्रदेश को संवैधानिक संकट की स्थिति में पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता मानीय सर्वोच्च न्यायालय की आभारी हैं, जिसके हस्तक्षेप और आदेशों के बाद आज ये चुनाव संपन्न हो पा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि प्रदेश की जनता उसकी जनविरोधी नीतियों, झूठे वादों और विफल शासन से नाराज है और चुनावों में कांग्रेस के खिलाफ मतदान



कर रही है। इसी कारण कांग्रेस पार्टी और सरकार अब सत्ता, धनबल और प्रशासनिक दबाव का उपयोग कर नगर परिषदों, बीडीसी और जिला परिषदों में पिछला दरवाजा अपनाकर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। डॉ. बिंदल ने कहा कि 17 मई को नगर निकाय चुनाव सम्पन्न हुए, लेकिन चुने हुए पार्षदों की अधिसूचना समय पर जारी नहीं की गई। भाजपा को इस विषय पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा, जिसके बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसके बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनावों को लेकर वर्षों से चली आ रही प्रक्रिया में अचानक बदलाव कर दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 27 मई 2026 को अधिसूचना जारी कर नगर निकाय चुनाव नियमों में संशोधन कर दिए, जिनके अनुसार अध्यक्ष

एवं उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए बैठक बुलाने का अधिकार उपायुक्त को अपनी सुविधा अनुसार दे दिया गया। पहले निर्धारित समय-सीमा और प्रक्रिया के तहत चुनाव कराए जाते थे, लेकिन अब सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई है जिससे चुने हुए प्रतिनिधियों पर प्रभाव डालने और राजनीतिक दबाव बनाने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने के बाद किसी भी नियम या कानून में बदलाव करना लोकतांत्रिक परंपराओं और निर्वाचन व्यवस्था की भावना के विपरीत है। इसके

बाजूद कांग्रेस सरकार ने अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए नियमों में संशोधन कर दिया, जो अत्यंत चिंताजनक और निन्दनीय है।

डॉ. बिंदल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार जनता द्वारा दिए गए जनादेश को स्वीकार करने के बजाय उसे तोड़-मरोड़ कर अपने पक्ष में करने का षड्यंत्र रच रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने पंचायतों और नगर निकायों में कांग्रेस की नीतियों को नकार दिया है, लेकिन सरकार लोकतांत्रिक फैसले का सम्मान करने की बजाय सत्ता के दुरुपयोग में लगी हुई है।

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र, संविधान और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी। जनता के जनादेश के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या सत्ता के दुरुपयोग को भाजपा किसी भी स्तर में स्वीकार नहीं करेगी।

डॉ. बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा रचे जा रहे इस पूरे षड्यंत्र के राजनीतिक परिणाम भी सामने आएंगे और प्रदेश की जनता लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने वालों को उचित जवाब देगी।

मतदान लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत, हर नागरिक को इसका प्रयोग करना चाहिए : जे.पी. नड्डा

अपने गांव में मतदान कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी का सौभाग्य मिला : जे.पी. नड्डा

प्रथम न्यूज | बिलासपुर
30 मई (जितेंद्र गौतम)

भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने पंचायती राज चुनावों में मतदान करने के बाद प्रदेशवासियों से अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक नागरिक को अपने मतदाधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए और यही एक सशक्त एवं जागरूक लोकतंत्र की पहचान है। जे.पी. नड्डा ने कहा कि आज उन्हें अपने गांव में आकर मतदान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की असली शक्ति जनता के सहभागिता में निहित है और जब नागरिक बड़े-चढ़कर मतदान करते हैं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था और अधिक मजबूत होती है।

उन्होंने प्रदेश की जनता से आग्रह करते हुए कहा कि सभी मतदाता अपने मत का अधिकार अवश्य प्रयोग करें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएं। उन्होंने कहा कि मतदान केवल



अधिकार ही नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी है, जिसके माध्यम से नागरिक अपने गांव, क्षेत्र और प्रदेश के विकास की दिशा तय करते हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं लोकतंत्र की बुनियाद हैं और ग्रामीण विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए इन चुनावों में अधिक से अधिक मतदान होना आवश्यक है ताकि जनता की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित हो सके। जे.पी. नड्डा ने विश्वास व्यक्त किया कि

तकनीकी शिक्षा मंत्री ने अपनी गृह पंचायत पनौल के मतदान केंद्र में डाला वोट

प्रथम न्यूज | बिलासपुर
30 मई (जितेंद्र गौतम)

नगर व ग्राम नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने आज घुमरावी विकास खंड के अंतर्गत अपनी गृह पंचायत पनौल के मतदान केंद्र में धर्मपत्नी सोनिया धर्माणी के साथ पंचायतीराज संस्थाओं के अंतिम चरण के चुनाव में मतदान किया।

इस अवसर पर उन्होंने लोकतंत्र के इस महान पर्व को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी की भागीदारी से ही हमारा लोकतांत्रिक ढांचा अधिक सशक्त एवं मजबूत बनता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का यह पर्व प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह पंचायतीराज संस्थाओं से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक अपने प्रतिनिधियों का चयन कर सके। उन्होंने कहा कि पंचायतीराज संस्थाओं के लिए प्रतिनिधियों का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पंचायतीराज व्यवस्था आम



नागरिकों के सबसे निकट उपलब्ध शासन व्यवस्था है।

राजेश धर्माणी ने युवा मतदाताओं से अपेक्षा व्यक्त करते हुए कहा कि वे ऐसे उम्मीदवारों का चयन करें जो जनता के प्रति समर्पित हों, जिनकी स्पष्ट सोच हो तथा जो अपने विजन को धरातल पर उतारने की क्षमता रखते हों। उन्होंने कहा कि युवा ही बदलाव के वाहक होते हैं। प्रदेश को आत्मनिर्भर तथा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने और समाज में बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए युवाओं को अपने घर के निकट सरकार की महत्वपूर्ण इकाई पंचायतीराज संस्थाओं के साथ-साथ विधानसभा एवं लोकसभा के लिए भी योग्य उम्मीदवारों का चयन करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि जितना बेहतर जनप्रतिनिधि होगा, उतनी ही बेहतर प्रशासनिक एवं विकासात्मक व्यवस्था सुनिश्चित होगी।

उन्होंने पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के माध्यम से चुने जाने वाले सभी प्रतिनिधियों से अपेक्षा जताई कि वे लोकतांत्रिक मूल्यों एवं जनहित की भावना को केंद्र में रखकर कार्य करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो उम्मीदवार इस चुनाव में सफल नहीं हो पाए हैं, वे भी समाज और देश के बेहतर उत्थान के लिए आगे भी सक्रिय रूप से कार्य करते रहें।

विकास खंड नालागढ़ में पंचायती राज संस्थाओं के तीनों चरणों के चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न

प्रथम न्यूज | नालागढ़
30 मई (गुरजीत सिंह)



मतदाता थे। इनमें से 16,985 पुरुष तथा 16,744 महिला मतदाताओं ने अपने मतदाधिकार का प्रयोग किया। इस प्रकार कुल मतदान प्रतिशत 86.99 दर्ज किया गया। पुरुष मतदाताओं का मतदान प्रतिशत 85.87 तथा महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत 88.47 रहा। महिलाओं की उल्लेखनीय भागीदारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति उनकी जागरूकता, विश्वास एवं सक्रिय सहभागिता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों के तीनों चरणों को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने में प्रशासन, पुलिस विभाग, विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, चुनाव द्यूटी में तैनात कार्मिकों तथा मतदाताओं का सराहनीय सहयोग प्राप्त हुआ। सभी के समन्वित प्रयासों से चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाया जा सका। निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि तृतीय चरण में हुए प्रधान, उपप्रधान एवं वार्ड सदस्य पदों के परिणाम 30 मई, 2026 को ही घोषित किए वहाँ पंचायत समिति सदस्य तथा जिला परिषद सदस्य की मतगणना 31 मई, 2026 को राजकीय महाविद्यालय नालागढ़ में प्रातः 8:00 बजे से शुरू की जाएगी, जिसके उपरांत परिणाम घोषित किए जाएंगे।

के प्रति उनकी जागरूकता, विश्वास एवं सक्रिय सहभागिता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों के तीनों चरणों को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने में प्रशासन, पुलिस विभाग, विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, चुनाव द्यूटी में तैनात कार्मिकों तथा मतदाताओं का सराहनीय सहयोग प्राप्त हुआ। सभी के समन्वित प्रयासों से चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाया जा सका। निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि तृतीय चरण में हुए प्रधान, उपप्रधान एवं वार्ड सदस्य पदों के परिणाम 30 मई, 2026 को ही घोषित किए वहाँ पंचायत समिति सदस्य तथा जिला परिषद सदस्य की मतगणना 31 मई, 2026 को राजकीय महाविद्यालय नालागढ़ में प्रातः 8:00 बजे से शुरू की जाएगी, जिसके उपरांत परिणाम घोषित किए जाएंगे।



संक्षिप्त न्यूज

2015 बैच के साथियों के लिए बड़ी खुशखबरी!



चंडीगढ़ (सुरिन्दर पाल) - आज टीचर्स यूनिवर्सिटी ऑफ सिटी ब्यूटीफुल के एक प्रतिनिधि मंडल को माननीय शिक्षा सचिव श्रीमती प्रेरणा पुरी, आईएएस से भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। इस अवसर पर अध्यक्ष (नामित) श्री पी.के. राव के नेतृत्व में श्रीमती पूनम शर्मा, श्री अभिषेक वत्स, श्रीमती रुपाली शर्मा, श्री गुलशन कुमार तथा केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य श्री संदीप कुमार एवं श्रीमती सुधा मेहता (सभी वर्तमान में नामित हैं क्योंकि अभी चुनाव होना शेष है) ने 2015 बैच के कर्मचारियों के बकाया परियर जारी करने तथा वेतन वृद्धि (इन्क्रोमेंट) बहाल करने संबंधी मांगों का ज्ञापन किया।

इन मांगों पर माननीय शिक्षा सचिव महोदय ने अत्यंत सुखद समाचार देते हुए बताया कि केवल एक औपचारिक प्रक्रिया पूरी होते ही परियर की पहली किस्त बहुत जल्द जारी कर दी जाएगी।

माननीय शिक्षा सचिव महोदय ने शिक्षकों की समस्याओं को धैर्य, संवेदनशीलता और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ सुना। शिक्षकों के कल्याण एवं शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता वास्तव में सराहनीय है। प्रतिनिधि मंडल शिक्षकों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर समय देने, सकारात्मक आश्वासन प्रदान करने तथा सहयोगात्मक रवैये के लिए माननीय महोदय का हार्दिक आभार व्यक्त करता है।

तंबाकू सेवन के हानिकारक प्रभावों पर प्रकाश डाला गया



चंडीगढ़ (जगमोत घुमन) - विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर, मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, मोहाली ने तंबाकू सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाई और जानलेवा बीमारियों, विशेष रूप से कैंसर से बचाव के लिए इसे छोड़ने के महत्व पर बल दिया। मैक्स की ऑन्कोलॉजी सलाहकार डॉ. आकांक्षा ने कहा, तंबाकू का सेवन, चाहे धूम्रपान के माध्यम से हो या धूम्रपान रहित माध्यमों से, कैंसर और हृदय रोग एवं फेफड़ों के विकारों सहित अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के प्रमुख कारणों में से एक है। व्यापक जागरूकता के बावजूद इसका उपयोग एक गंभीर जन स्वास्थ्य चिंता का विषय बना हुआ है।

उन्होंने आगे कहा, तंबाकू कई प्रकार के कैंसर, जिनमें मुँह, फेफड़े और गले का कैंसर शामिल है, के लिए सबसे बड़े जोखिम कारकों में से एक है। अच्छी खबर यह है कि किसी भी अवस्था में तंबाकू छोड़ने से इन जोखिमों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। जागरूकता, प्रारंभिक जांच और समय पर हस्तक्षेप जीवन बचा सकते हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि तंबाकू से जुड़े कैंसर के कई मामलों को रोका जा सकता है, विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए जिनका तंबाकू सेवन का इतिहास रहा है।

मिल परिसर में पक्षियों के लिए रखवाए पानी के कसोरे, कर्मचारियों ने लिया नियमित रूप से पानी भरने का संकल्प

कैथल, 30 मई (कृष्ण गर्ग) भीषण गर्मी और लू के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कैथल सहकारी चीनी मिल प्रशासन ने पक्षियों के संरक्षण एवं उनकी प्यास बुझाने के लिए मिल परिसर में विभिन्न स्थानों पर पानी से भरे कसोरे रखवाए। इस दौरान मिल कर्मचारियों ने इन कसोरों में नियमित रूप से पानी भरने का संकल्प भी लिया।

मिल के प्रबंध निदेशक कृष्ण कुमार ने कहा कि गर्मी के मौसम में पक्षियों को पानी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे में प्रत्येक नागरिक को अपने घरों, कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर पक्षियों के लिए पानी एवं दाने की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह छोटी-सी पहल हजारों बेजुबान पक्षियों के जीवन की रक्षा करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। प्रकृति और जीव-जंतुओं का संरक्षण हम सभी का नैतिक दायित्व है।

उन्होंने कर्मचारियों से आह्वान किया कि वे पर्यावरण संरक्षण और जीवों के प्रति संवेदनशीलता का परिचय देते हुए इस अभियान को जन-जन तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए प्रेरित हों।

प्रबंध निदेशक ने क्षेत्र में पड़ रही भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर कर्मचारियों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि कर्मचारी कार्य के दौरान पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें, तेज धूप में अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें तथा हल्के और सूती वस्त्र पहनें। उन्होंने बहर निकलते समय सिर को कपड़े से ढकने की भी सलाह दी। इस अवसर पर मुख्य लेखाधिकारी सतीश कुमार, मुख्य रसायनविद कमलकान्त तिवारी, उप मुख्य अभिन्ता ए.एच. जुबैरी, विच्री प्रबंधक जगदीश कासवान, लवलेश शर्मा, रामपाल तंवर, शमशेर कुंडू, सुरेश शर्मा, सुशील तंवर, उपन शर्मा सहित मिल के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।



2029 तक किए गए सभी वादे किए जाएंगे पूरे : नायब सिंह सैनी

बाबा साहेब संविधान निर्माता ही नहीं, बल्कि करोड़ों वंचितों के सपनों के भी निर्माता, 29 जून को भिवानी में मनाई जाएगी संत कबीर जयंती - मुख्यमंत्री

प्रथम न्यूज | चंडीगढ़
30 मई (मुकेश डोलिया)

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार धानक समाज के सम्मान की प्रहरी है। समाज के अधिकारों की रक्षा करना, बच्चों को बेहतर भविष्य देना और समाज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री शनिवार को चण्डीगढ़ में धानक समाज के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इसमें हरियाणा, चंडीगढ़ के अलावा पंजाब के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 29 जून को भिवानी में संत कबीरदास जयंती मनाई जाएगी। इसी तरह पंजाब के अबोहर और लुधियाना में भी आयोजित की जाने वाली जयंती समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनकी हर समस्या का निराकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2029 तक भाजपा सरकार द्वारा किए गए सभी वादे पूरे किए जाएंगे। अब तक 63 संकल्पों पर गति से कार्य चल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि धानक समाज का इतिहास स्वार्थिता, त्याग और राष्ट्र निर्माण का रहा है। चाहे देश की आजादी की लड़ाई हो, समाज सुधार का आंदोलन हो या आज के विकसित भारत के निर्माण की यात्रा हो, समाज हर मोर्चे पर अग्रणी रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सामाजिक न्याय, आत्म-सम्मान और अधिकारों की आवाज को और अधिक मजबूत करने का



अवसर है। संत कबीर दास की विरासत के ध्वजवाहक बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके हाथों की मेहनत, माथे का पसीना और आगे बढ़ने का जज्बा ही समाज की ताकत है और यहीं विरासत है। संत कबीर दास का भी यही संदेश था कि श्रम ही सम्मान का सबसे बड़ा आधार है। उन्होंने कहा कि दशकों तक कुछ राजनीतिक दलों ने समाज को केवल वोट बैंक समझा। चुनाव के समय बड़े-बड़े वादे किए, लेकिन जब अधिकार देने की बात आई, तब केवल आश्वासन मिले। उन्होंने कहा कि हरियाणा में डबल इंजन सरकार राष्ट्र व समाज हित में ठोस निर्णय लेने वाली है। अनुसूचित जाति समाज के भीतर उन वर्गों की पीड़ा को समझा, इसलिए विधानसभा चुनाव के दौरान संकल्प-पत्र में अनुसूचित जातियों के आरक्षण को वंचित अनुसूचित जाति और अन्य अनुसूचित जाति में विभाजित करने का वादा कर उसे धरातल पर

लागू करने का कार्य किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 20 प्रतिशत कोटे में से 10 प्रतिशत हिस्सा विशेष रूप से वंचित अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किया है। यह सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि जब भी हम गरीब, वंचित और शोषित समाज के अधिकारों की बात करते हैं, तब बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर का महान व्यक्तित्व हमारे सामने खड़ा दिखाई देता है। बाबा साहेब केवल संविधान निर्माता नहीं थे, वे करोड़ों वंचितों के सपनों के निर्माता भी थे। उन्होंने हमें संविधान में हर व्यक्ति को समान अधिकार, समान अवसर और सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया। उनका दिया मंत्र शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो आज भी किसी भी समाज के विकास का मार्गदर्शक सिद्धांत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसी मंत्र को आत्मसात करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका

प्रयास का विजन राष्ट्र को दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीब के घर तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया। आज गरीब का बेटा भी डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक अधिकारी बन रहे हैं। यह परिवर्तन केवल नीतियों से नहीं, बल्कि नीयत से आया है। हरियाणा में भाजपा सरकार ने मजबूत इरादों के साथ कार्य किया है। हरियाणा पुलिस भर्ती में 604 बच्चे डी.एस.सी. समाज से भर्ती हुए। कांग्रेस ने केवल 100-100 वर्ग गज के प्लॉट देने की घोषणा की थी लेकिन, हमारी सरकार ने कांग्रेस के समय के वंचितों को प्लॉटों के कागज व कब्जे दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने जरूरतमंद 16 हजार 500 परिवारों को अलग से 100-100 वर्ग गज के प्लॉट दिए और प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़कर इन प्लॉटों पर मकान बनवाकर इनकी चाबियां पात्र परिवारों को सौंपी। पिछले साढ़े 11 सालों में 1 लाख 60 हजार मकान पात्र परिवारों को दिए हैं। पिछले दिनों

सोनीपत व गुरुग्राम में 3250 प्लैट भी पात्र परिवारों को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब धन के अभाव में कोई भी गरीब इलाज से वंचित नहीं रहेगा। आयुष्मान भारत-चिरायु योजना में 29 लाख 20 हजार 806 मरीजों का 4 हजार 131 करोड़ रुपये से मुफ्त इलाज किया गया है। डायलिसिस की सुविधा हर जिला स्तर के अस्पताल में देने वाला हरियाणा पहला राज्य है। अब तक दो लाख रोगियों ने इस योजना का लाभ उठाया है। इसके अलावा बुजुर्गों को 3200 रुपए पेंशन तथा लाडो-लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर माह 2100 रुपए दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने जरूरतमंद 16 हजार 500 परिवारों को अलग से 100-100 वर्ग गज के प्लॉट दिए और प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़कर इन प्लॉटों पर मकान बनवाकर इनकी चाबियां पात्र परिवारों को सौंपी। पिछले साढ़े 11 सालों में 1 लाख 60 हजार मकान पात्र परिवारों को दिए हैं। पिछले दिनों

चंडीगढ़ सेक्टर-26 थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई
11.56 ग्राम हेरोइन सहित आरोपी गिरफ्तार

प्रथम न्यूज | चंडीगढ़
30 मई (पुनीत महाजन)

चंडीगढ़ पुलिस द्वारा नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना सेक्टर-26 पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अवैध रूप से मादक पदार्थ रखने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 11.56 ग्राम हेरोइन (डायएसिटाइलमॉर्फिन) बरामद की है। पुलिस अधीक्षक (सिटी) के निदेशान तथा एसडीपीओ ईस्ट की निगरानी में थाना सेक्टर-26 की टीम ने यह कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपी की पहचान गुलशन पुत्र सुरेश बदनान, निवासी मकान नंबर 725/11, बापू धाम

कॉलोनी, सेक्टर-26, चंडीगढ़ के रूप में हुई है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 29 मई 2026 को एसआई अजय कुमार अपनी पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे। इस दौरान सेक्टर-26 स्थित बापू धाम कॉलोनी के ब्लॉक नंबर 725 के पास सतिश अवस्था में घूम रहे आरोपी गुलशन को रोका गया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 11.56 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। आरोपी बरामद मादक पदार्थ के संबंध में कोई वैध लाइसेंस या अनुमति पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद आरोपी के खिलाफ थाना सेक्टर-26 में एफआईआर नंबर 68 दिनांक 30 मई 2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा

21 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान आरोपी को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी पहले भी चोरी, हथियार अधिनियम तथा एनडीपीएस एक्ट सहित विभिन्न मामलों में संलिप्त रहा है और उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस आज आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश करेगी तथा हेरोइन की स्प्लॉई चैन और स्रोत का पता लगाने के लिए पुलिस रिमांड की मांग करेगी। मामले की जांच जारी है। चंडीगढ़ पुलिस ने कहा है कि शहर को नशामुक्त बनाने के लिए नशा तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी इसी प्रकार जारी रहेगा।

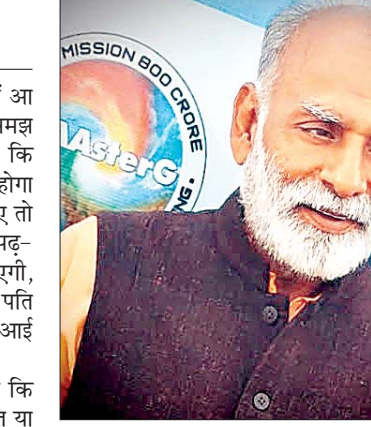


पदार्थों में शांति होती तो जिनके पास सब कुछ है शांत होते, शांति का वास्तविक अर्थ शांति क्या है?

प्रथम न्यूज | चंडीगढ़
30 मई (मुकेश डोलिया)

संसार का जो पूरा खेल है, वो अगर समझ में आ जाए, तो जीवन बहुत आनंद से भरा है, और यदि समझ में ना आए, तो दुख ही दुख है। हम सोचते हैं कि जीवन में शांति होगी अगर हमारे पास सब कुछ होगा जैसे घर, गाड़ी, पैसा; हम सोचते हैं कि ये हो जाए तो शांति आ जाएगी, अच्छे परिवार हो जाए, बच्चे पढ़-लिख जाएँ, नौकरी लग जाए तो शांति आ जाएगी, अच्छी बहू आ जाए तो शांति आ जाएगी, अच्छे पति मिल जाए तो शांति आ जाएगी; पर संसार में शांति आई तो नहीं, सब अशांत ही हैं।

घर में हवन कराते हैं जब गृह प्रवेश होता है कि शांति रहेगी लेकिन शांति आती तो नहीं। तो शांति या तो इन सब पदार्थों से आए, या इन सब शक्तों से आए, या इन पूजा-पाठ से आए क्योंकि पूजा-पाठ भी शांति के लिए कर रहे हैं, हवन शांति के लिए होता है, पर किसी घर में शांति है? कभी सोचा कि 2500 साल पहले बुद्ध ने क्यों कह दिया कि संसार दुख है; गुरु नानक देव ने 500 साल पहले क्यों कहा दुखिया सकल संसार। इसका अर्थ है कि संसार में जहाँ हम दूढ़ रहे



हैं वहाँ शांति नहीं है, तो शांति है कहाँ? अगर पदार्थों में शांति होती तो जिनके पास सब कुछ है शांत होते, अगर शक्तों में शांति होते तो सबके पास शक्तें हैं, संबंध है, सबको शांति मिल जाती लेकिन नहीं मिली। तो कहा कि जिन खोजा तिन पाइयों गहरे पानी पेट, यानी जो गहरे में गया है उसने जाना है कि शांति कहाँ है। ये शांति जानी बुद्ध, महावीर, जीसस, गुरु नानक

देव, साई बाबा, मीराबाई, सहजोबाई, लखन बाई ने; ये शांति उन्होंने जानी और जब उन्होंने जाना तो उन्होंने संसार को ज्ञान दिया कि तुम क्या कर रहे हो! ये जो तुम बंगले, गाड़ी, दौलत, संबंध, पदार्थों के लिए भाग रहे हो, ये हो जाए वो हो जाए, इसमें शांति नहीं है। शांति है अगर तुम इस सारे खेल को टेंप्रेरी समझ लो, खेल समझ लो। इस खेल में जो लोग तुम्हारे पास हैं, सब प्यारे हैं; यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है कि तुम कुछ करते हो, बल्कि सब कुछ तुमसे करवाया जा रहा है। तुम तो हिल भी नहीं सकते उस एक परमात्मा के बिना, कुछ देख भी नहीं सकते उसके बिना, ये तुझे दिखाया जा रहा है, तुझे चलाया जा रहा है, तुझे खिलाया जा रहा है, तुझे सुलाया जा रहा है। ये सब खेल नियमित है, कुछ भी तुम्हारा नहीं है। सुनते तो हम थे ना कि उसकी मर्जी के बिना पता भी नहीं हिलता, पर पता नहीं हिलता तो तुम कैसे हिल सकते हो? तुम तो कहते हो की सब कुछ मैं चलता हूँ, मेरी मर्जी से सब चलना चाहिए। जब उसकी मर्जी के बिना पता भी नहीं हिलता, तो तुम क्यों अपनी मर्जी बीच में लाते हो। जब तुम्हारी मर्जी आती है तो अशांति आ जाती है, उसकी मर्जी आती है तो शांति आ जाती है।

राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस-1933 पर दे ड्रग्स तस्करी की गुप्त जानकारी : डीसी अपराजिता

कैथल, 30 मई (कृष्ण गर्ग)

डीसी अपराजिता ने बताया कि केंद्र सरकार ने नशे के खिलाफ राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस-1933 शुरू किया हुआ है। यह हेल्पलाइन देश को 2047 तक नशा मुक्त बनाने के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मानस हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे चालू रहेगा है लोग इस पर ड्रग्स तस्करी की गुप्त जानकारी साझा कर सकते हैं। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि नशा न केवल व्यक्ति के शरीर व बुद्धि का नाश करता है, बल्कि समाज को भी खोखला करता है। नशा करने वाले व्यक्ति का पूरा परिवार इससे प्रभावित होता है। केंद्र सरकार की मानस पहल से नशा बचने वालों पर नकेल कसी जाएगी और नशे की लत से जुड़ रहे लोगों को मुक्तधारा में लाने का प्रयास किया जाएगा। नशे की लत छुड़ाने के लिए कारंसेलिंग और पुनर्वास की सुविधा भी उपलब्ध होगी। डीसी अपराजिता ने बताया कि यह हेल्पलाइन देशभर की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स से जुड़ी है ताकि तस्करी पर तुरंत कार्रवाई हो सके। इस प्लेटफॉर्म की पहुंच बढ़ाने और त्वरित प्रतिक्रिया की सुविधा के लिए इस हेल्पलाइन के बारे में आमजन को जागरूक किया जा रहा है, ताकि वे नशीली दवाओं की तस्करी संबंधित रिपोर्टें दे सकें और नशे की लत में पड़ चुके लोग परामर्श ले सकें। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि वे नशा को वर्ष 2047 तक नशा मुक्त बनाने के राष्ट्रीय दृष्टिकोण में अपना सक्रिय योगदान दें।



कानून व्यवस्था, नीट परीक्षा व नशामुक्त हरियाणा पर डीजीपी की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक

प्रथम न्यूज | चंडीगढ़
30 मई (सुरिन्दर पाल)

हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने प्रदेश में कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, नीट परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था तथा नशामुक्त हरियाणा अभियान को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रदेशभर के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। डीजीपी ने सभी अधिकारियों को राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप गंभीरता, सतर्कता और योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने के निर्देश दिए।

नीट परीक्षा को लेकर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने के निर्देश - बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीजीपी ने कहा कि आगामी 21 जून को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाना हरियाणा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वयं इस विषय को गंभीरता से मॉनिटर कर रहे हैं और परीक्षा प्रक्रिया पर केंद्र एवं राज्य स्तर



पर निरंतर निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परीक्षा केंद्रों का समय रहते निरीक्षण किया जाए तथा सुरक्षा, निगरानी एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को पहले से सुनिश्चित किया जाए। डीजीपी ने विशेष रूप से खुफिया तंत्र को सक्रिय रखने के निर्देश देते हुए कहा कि पेपर लीक अथवा किसी भी प्रकार की अनियमितता पर हरियाणा पुलिस को नजर रहनी चाहिए तथा उन्हें रोकने के भरपूर प्रयास होने चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस मामले में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

नशामुक्त हरियाणा अभियान को बड़े स्तर पर चलाने की तैयारी - बैठक में नशामुक्त हरियाणा अभियान को लेकर भी व्यापक चर्चा की गई। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, हरियाणा रहते निरीक्षण किया जाए तथा सुरक्षा, निगरानी एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को पहले से सुनिश्चित किया जाए। डीजीपी ने विशेष रूप से खुफिया तंत्र को सक्रिय रखने के निर्देश देते हुए कहा कि पेपर लीक अथवा किसी भी प्रकार की अनियमितता पर हरियाणा पुलिस को नजर रहनी चाहिए तथा उन्हें रोकने के भरपूर प्रयास होने चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस मामले में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

गए। उन्होंने बताया कि जल्द ही राज्य स्तर पर विशेष अभियान प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री स्वयं विभिन्न जिलों का दौरा कर लोगों को जागरूक करेंगे। नशा तस्करी के नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश - एडीजीपी संजय कुमार ने कहा कि पड़ोसी राज्यों में बढ़ती नशा तस्करी का सीधा प्रभाव हरियाणा पर पड़ता है। ऐसे में डिमांड और सप्लाई दोनों स्तरों पर रणनीतिक कार्रवाई करना आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नशा विच्री अथवा स्ट्रेजेज की सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि मैडिकल स्टोर एवं कैमिस्ट एसोसिएशन के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाएं तथा कैमिस्ट शॉप के स्टॉक, सीसीटीवी सिस्टम और रिकॉर्ड की लगातार निगरानी की जाए। निरंतर जांच अभियान से नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा।

नाकों ड्रांस और तकनीकी निगरानी से बड़ेगी कार्रवाई की प्रभावशीलता : बैठक में बताया गया कि हरियाणा पुलिस के नाकों ड्रांस नशा तस्करी से जुड़े मामलों में प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। कई बड़े मामलों में उनकी सहायता से महत्वपूर्ण सफलता मिली है। जिलों को आवश्यकतानुसार नाकों ड्रांस की सहायता लेने के निर्देश दिए गए। एडीजीपी संजय कुमार ने जानकारी दी कि पिछले पांच वर्षों में कमर्शियल क्राइटी के मामलों में कुल 3062 अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जबकि वर्ष 2023 से अब तक पीआईटी-एनडीपीएस के तहत 153 लोगों को हिरासत में लिया गया है। नशे से अर्जित संपत्ति पर भी होगी कार्रवाई : डीजीपी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नशा तस्करी में बार-बार संलिप्त पाए जाने वाले अपराधियों की गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाए। उन्होंने कहा कि कमर्शियल क्राइटी के मामलों में अपराध से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने सभी जिलों को निर्देश दिए कि अगले 15 दिनों के भीतर कमर्शियल क्राइटी के मामलों में शामिल अपराधियों का सत्यापन कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें।



आज का संपादकीय

विश्व तंबाकू निषेध दिवस

हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा चलाया जाने वाला एक वैश्विक स्वास्थ्य अभियान है, जिसका उद्देश्य तंबाकू के सेवन के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसके सेवन को कम करने के लिए प्रभावी नीतियों का समर्थन करना है। इसे तंबाकू विरोधी दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह दिवस तंबाकू के सेवन के विनाशकारी स्वास्थ्य, सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक परिणामों और तंबाकू एक निर्यात उत्पादों से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट को एक सशक्त याद दिलाता है, जिसके कारण प्रतिवर्ष 87 लाख से अधिक लोगों की जान जाती है। तंबाकू विरोधी दिवस 2026 न केवल कार्बोहाइड्रेट का आह्वान है, बल्कि यह इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि कैसे यह उद्योग छल और धोखे के माध्यम से युवाओं को निशाना बनाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2026 का विषय अपमान का पर्दाफाश है, जो इस बात पर केंद्रित है कि कैसे उद्योग स्वादयुक्त उत्पादों, भ्रामक विपणन और व्यसनकारी उत्पाद डिजाइनों के माध्यम से युवाओं को लक्षित करके उन्हें आजीवन उपयोगकर्ता बनाते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस की अवधारणा सर्वप्रथम 1987 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के सदस्य देशों द्वारा रखी गई थी। प्रारंभ में 7 अप्रैल 1988 को इसे विश्व धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया गया, लेकिन बाद में प्रत्येक वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया।



शशि पाल
प्रवक्ता इतिहास

सेवन बंद करना मुश्किल हो जाता है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज अध्ययन के अनुसार, तंबाकू के सेवन से प्रतिवर्ष लगभग 87 लाख मौतें होती हैं। इनमें से 77 लाख मौतें धूम्रपान के कारण होती हैं, जबकि 13 लाख मौतें परोक्ष धूम्रपान के संपर्क में आने से होती हैं।

भारत में 253 मिलियन से अधिक तंबाकू उपयोगकर्ता हैं, जो इसे उपयोगकर्ता आबादी के मामले में विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा देश बनाता है। तंबाकू का सेवन भारत में बीमारियों के बोझ और असमय मृत्यु दर में भारी योगदान देता है। इस्केमिक हृदय रोग से होने वाली मौतों में से 18% , स्ट्रोक से होने वाली मौतों में से 14.2% और फेफड़ों के कैंसर से होने वाली मौतों में से 60.4% के लिए तंबाकू जिम्मेदार है। छोड़ो तंबाकू, अपनाओ खुशियाँ।

हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा चलाया जाने वाला एक वैश्विक स्वास्थ्य अभियान है, जिसका उद्देश्य तंबाकू के सेवन के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसके सेवन को कम करने के लिए प्रभावी नीतियों का समर्थन करना है। इसे तंबाकू विरोधी दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह दिवस तंबाकू के सेवन के विनाशकारी स्वास्थ्य, सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक परिणामों और तंबाकू एक निर्यात उत्पादों से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट को एक सशक्त याद दिलाता है, जिसके कारण प्रतिवर्ष 87 लाख से अधिक लोगों की जान जाती है। तंबाकू विरोधी दिवस 2026 न केवल कार्बोहाइड्रेट का आह्वान है, बल्कि यह इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि कैसे यह उद्योग छल और धोखे के माध्यम से युवाओं को निशाना बनाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2026 का विषय अपमान का पर्दाफाश है, जो इस बात पर केंद्रित है कि कैसे उद्योग स्वादयुक्त उत्पादों, भ्रामक विपणन और व्यसनकारी उत्पाद डिजाइनों के माध्यम से युवाओं को लक्षित करके उन्हें आजीवन उपयोगकर्ता बनाते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस की अवधारणा सर्वप्रथम 1987 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के सदस्य देशों द्वारा रखी गई थी। प्रारंभ में 7 अप्रैल 1988 को इसे विश्व धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया गया, लेकिन बाद में प्रत्येक वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया।

1988 में, विश्व स्वास्थ्य सभा ने आधिकारिक तौर पर संकल्प WHA42.19 पारित किया, जिसमें 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में नामित किया गया। इसका उद्देश्य जनता को तंबाकू के खतरों के बारे में सूचित करना, तंबाकू उद्योग की अनैतिक रणनीति को उजागर करना और तंबाकू

के उपयोग को कम करने के लिए वैश्विक कार्रवाई को बढ़ावा देना है। तंबाकू निकोटिनिया ना पौधे की पत्तियों से प्राप्त होता है और इसमें निकोटिन नामक एक अत्यधिक व्यसनकारी पदार्थ होता है। इसका सेवन सिगरेट, सिगार, पाइप तंबाकू और धुआँ रहित तंबाकू (जैसे भारत में गुटखा और खैनी) जैसे विभिन्न रूपों में किया जाता है।

तंबाकू सेवन के प्रभाव

प्रत्यक्ष स्वास्थ्य परिणाम : फेफड़ों का कैंसर, हृदय रोग, स्ट्रोक, क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी), और अन्य।

परोक्ष धूम्रपान : इससे प्रतिवर्ष लगभग 13 लाख मौतें होती हैं, जिनमें से 65,000 बच्चे इसके संपर्क में आने से संबंधित बीमारियों के कारण मर जाते हैं।

गर्भावस्था के जोखिम : गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान करने से शिशुओं का जन्म के समय वजन कम हो सकता है, समय से पहले प्रसव हो सकता है और उनमें विकास संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।

लत और निर्भरता : निकोटिन मस्तिष्क को रासायनिक संरचना को बदल देता है, जिससे इसका सेवन बंद करना मुश्किल हो जाता है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज अध्ययन के अनुसार, तंबाकू के सेवन से प्रतिवर्ष लगभग 87 लाख मौतें होती हैं। इनमें से 77 लाख मौतें धूम्रपान के कारण होती हैं, जबकि 13 लाख मौतें परोक्ष धूम्रपान के संपर्क में आने से होती हैं।

भारत में 253 मिलियन से अधिक तंबाकू उपयोगकर्ता हैं, जो इसे उपयोगकर्ता आबादी के मामले में विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा देश बनाता है। तंबाकू का सेवन भारत में बीमारियों के बोझ और असमय मृत्यु दर में भारी योगदान देता है। इस्केमिक हृदय रोग से होने वाली मौतों में से 18% , स्ट्रोक से होने वाली मौतों में से 14.2% और फेफड़ों के कैंसर से होने वाली मौतों में से 60.4% के लिए तंबाकू जिम्मेदार है।

छोड़ो तंबाकू, अपनाओ खुशियाँ।

हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा चलाया जाने वाला एक वैश्विक स्वास्थ्य अभियान है, जिसका उद्देश्य तंबाकू के सेवन के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसके सेवन को कम करने के लिए प्रभावी नीतियों का समर्थन करना है। इसे तंबाकू विरोधी दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह दिवस तंबाकू के सेवन के विनाशकारी स्वास्थ्य, सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक परिणामों और तंबाकू एक निर्यात उत्पादों से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट को एक सशक्त याद दिलाता है, जिसके कारण प्रतिवर्ष 87 लाख से अधिक लोगों की जान जाती है। तंबाकू विरोधी दिवस 2026 न केवल कार्बोहाइड्रेट का आह्वान है, बल्कि यह इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि कैसे यह उद्योग छल और धोखे के माध्यम से युवाओं को निशाना बनाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2026 का विषय अपमान का पर्दाफाश है, जो इस बात पर केंद्रित है कि कैसे उद्योग स्वादयुक्त उत्पादों, भ्रामक विपणन और व्यसनकारी उत्पाद डिजाइनों के माध्यम से युवाओं को लक्षित करके उन्हें आजीवन उपयोगकर्ता बनाते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस की अवधारणा सर्वप्रथम 1987 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के सदस्य देशों द्वारा रखी गई थी। प्रारंभ में 7 अप्रैल 1988 को इसे विश्व धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया गया, लेकिन बाद में प्रत्येक वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया।

1988 में, विश्व स्वास्थ्य सभा ने आधिकारिक तौर पर संकल्प WHA42.19 पारित किया, जिसमें 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में नामित किया गया। इसका उद्देश्य जनता को तंबाकू के खतरों के बारे में सूचित करना, तंबाकू उद्योग की अनैतिक रणनीति को उजागर करना और तंबाकू

बेशक, हर साल 31 मई को विश्व धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। मंच पर भाषण होते हैं, पोस्टर लगते हैं, स्कूलों और सरकारी दफ्तरों में शपथ ली जाती है। एक दिन के लिए तंबाकू के दुष्प्रभावों की चर्चा होती है और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। यही सबसे बड़ी विडम्बना है। ऐसे दिवस अब धीरे-धीरे औपचारिकता भर रह गए हैं। कैलेंडर पर तारीख बदलती है, पर जमीन पर हालात नहीं बदलते। धरातल की सच्चाइयाँ बहुत ही भयानक हैं—तंबाकू हर साल लाखों घर उजाड़ रहा है, युवा पीढ़ी को अपनी गिरफ्त में ले रहा है और समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। कानून और अभियान अकेले इस समस्या को खत्म नहीं कर सकते। जब तक हर नागरिक इसे अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, तब तक ये दिवस सिर्फ एक रसम बनकर रह जायेगा। सार्थकता तभी आएगी जब हम जागरूकता को आदत में बदलें और अपने-अपने स्तर पर योगदान दें।

तंबाकू ने चुपचाप एक ऐसा जाल फैला रखा है जो दिखाई नहीं देता, पर उसकी पकड़ सबसे मजबूत है। शहर में पढ़ा-लिखा युवक जानता है कि सिगरेट कैंसर देती है, फिर भी दोस्तों के साथ एक कश लगाता है। गांव में बुजुर्ग कहता है कि हमारे बाप-दादा भी खाते थे, कुछ नहीं हुआ। दोनों ही भ्रम में हैं। धीरे-धीरे शरीर के अंदर घर बना लेता है। पहले सांस फूलती है, फिर खांसी पुरानी हो जाती है, और एक दिन पता चलता है कि बीमारी आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है। इलाज महंगा है, दर्दनाक है और अक्सर देर हो चुकी होती है। जो लोग बच भी जाते हैं, उनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। सबसे तालीफंदेदार बात यह है कि अब इस जाल में बच्चे और युवा फंस रहे हैं। पान मसाले का छोट्ट पकेट, रंगीन पैकेजिंग वाली ई-सिगरेट और वॉपिंग को कूल समझकर अपनाया जा रहा है। फिल्में और वेब सीरीज में नायक का सिगरेट सुलगाणा आज भी युवाओं के लिए स्टायल का प्रतीक बना हुआ है। पान की दुकान पर खुली बिस्की और सड़क किनारे आसानी से उपलब्धता ने इस लत को आम बना दिया है। जो उम्र पढ़ने, खेलने और सपने देखने की है, उसी उम्र में फेफड़े कमजोर हो रहे हैं और मुँह की बीमारियाँ घर कर रही हैं।

तंबाकू की लत सिर्फ शरीर की नहीं होती, यह मन की भी होती है। निकोटिन दिमाग में एक झूठी शांति का अहसास देता है। तनाव हो, बेरोजगारी हो, घर में

कलह हो या दोस्तों का दबाव-लोग एक कश में राहत ढूँढने लगते हैं। धीरे-धीरे यह राहत आदत बन जाती है और आदत लत। फिर व्यक्ति जानता है कि यह गलत है, पर छोड़ नहीं पाता। समाज ने भी इस आदत को सामान्य बना दिया है। शादी-विवाह में पान मसाले की ट्रे घूमती है, दफ्तर के बाहर स्मोक ब्रेक को हक समझा जाता है, और खेत में काम करने वाला मजदूर बीड़ी को थकान मिटाने का साधन मानता है। जब तक इस सामान्यीकरण को तोड़ा नहीं जाएगा, तब तक कानून और जागरूकता अभियान अपूर्ण रहेंगे। इसका असर सिर्फ पीने वाले पर नहीं पड़ता। घर में जब पिता या भाई सिगरेट सुलगाता है तो पूरे घर की हवा जहरीली हो जाती है। बच्चे, महिलाएँ और बुजुर्ग परोक्ष धूम्रपान के शिकार होते हैं। छोटे बच्चों में अस्थमा और निमोनिया की शिकायतें बढ़ रही हैं। गर्भवती महिलाओं का धूम्रपान करना अजन्मे बच्चे के विकास को नुकसान पहुंचाता है। तंबाकू गरीबी को भी बढ़ाता है। जो पैसा रोज गुटखा, खैनी या सिगरेट पर खर्च होता है, वही पैसा अगर बचाया जाए तो बच्चों को पढ़ाई, घर का राशन और दवा का इंतजाम हो सकता है। इस तरह तंबाकू न सिर्फ सेहत खीनता है, बल्कि सपनों को भी मार देता है।

सरकार ने कानून बनाए हैं। सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है, पैकेटों पर चेतावनी की तस्वीरें छपती हैं, कीमतें बढ़ाई जाती हैं। ये कदम जरूरी हैं, पर अकेले पर्याप्त नहीं। कानून डर पैदा कर सकता है, पर इच्छाशक्ति नहीं दे सकता। इच्छाशक्ति तभी आएगी जब व्यक्ति को लगे कि छोड़ना उसके अपने हित में है। और यह एहसास तभी जागेगा जब घर, स्कूल, समाज और दोस्त सब मिलकर उसे समझाएँ। बदलाव की शुरुआत घर से होती है। अगर माता-पिता बच्चों के सामने धूम्रपान नहीं करेंगे तो बच्चे उसे

सामान्य नहीं समझेंगे। स्कूलों को चाहिए कि वे सिर्फ डर दिखाने के बजाय छात्रों को तनाव से निपटने के तरीके सिखाएँ। योग, खेल, मेडिटेशन और काउंसलिंग जैसे विकल्प देने होंगे। दोस्तों के

दिलाले हैं, तो माहौल बदलता है। लोग शर्म की वजह से नहीं, सम्मान की वजह से छोड़ते हैं। यह रास्ता कठिन है, पर यही स्थायी है। मीडिया और सिनेमा की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। जब पढ़े पर नायक सिगरेट के कश के साथ डायलॉग बोलता है, तो लाखों युवा उसे अपनाते की कोशिश करते हैं। मनोरंजन के नाम पर इस आदत को महिमामंडित करना बंद होना चाहिए। इसके बजाय उन लोगों की कहानियाँ दिखाई जाएँ जिन्होंने तंबाकू छोड़कर अपनी जिंदगी बदली है। सकारात्मक उदाहरणों का अरार डवाने वाले विज्ञापनों से कहीं ज्यादा गहरा होता है। ग्रामीण इलाकों में स्थिति और जटिल है। वहाँ तंबाकू को थकान मिटाने और भूख दवाने का साधन माना जाता है। खेतों में काम करने वाले लोग दिनभर बीड़ी पीते हैं और समझते हैं कि इससे शरीर में ताकत आती है। असल में यह भ्रम है। तंबाकू शरीर को कमजोर करता है, सांस की बीमारियाँ बढ़ाता है और काम करने की क्षमता घटाता है। ऐसे में जागरूकता के साथ-साथ वैकल्पिक रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाएँ भी जरूरी हैं। जब तक गाँव का व्यक्ति यह महसूस नहीं करेगा कि तंबाकू छोड़ने से उसकी रोज की जिंदगी आसान होगी, तब तक वह इसे छोड़ेगा नहीं।

शरीर मध्यमवर्गीय परिवारों में भी समस्या अलग रूप में है। यहाँ लोग जानते हैं कि तंबाकू हानिकारक है, पर तनाव और प्रतिस्पर्धा के नाम पर इसे जायज ठहराते हैं। ऑफिस का दबाव, रात-रात भर जागना, परिवार को समय न दे पाना—इन सबका ठीकरा सिगरेट पर फोड़ दिया जाता है। जबकि सिगरेट यह है कि तंबाकू तनाव कम नहीं करता, बल्कि उसे बढ़ाता है। कुछ मिनट की राहत के बाद शरीर और मन दोनों और थक जाते हैं। इस पूरे परिदृश्य में सबसे जरूरी बात यह है कि हम तंबाकू को केवल स्वास्थ्य का मुद्दा न समझें। यह सामाजिक, आर्थिक और नैतिक सवाल भी है। एक परिवार जब तंबाकू पर पैसा खर्च करता है तो बच्चों की शिक्षा पीछे छूट जाती है। एक गाँव जब तंबाकू की लत में फँसता है तो विकास की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। एक समाज जब इसे सामान्य मान लेता है तो आने वाली पीढ़ी को गलत संदेश मिलता है। इसलिए विश्व धूम्रपान निषेध दिवस को सिर्फ एक तारीख न रहने दें। इसे आत्ममंथन का दिन बनाएँ। अपने आसपास देखें—क्या कोई दोस्त, रिश्तेदार या सहकर्मी इस लत में फँसा है? अगर हाँ, तो उसे डाँटने

को चाहिए कि तंबाकू खाने वाले को मदराना या स्टाइलिश समझने की मानसिकता बदले। असली मर्द वो है जो अपनी सेहत और परिवार के जिम्मेदारी उठा सके। मोहल्ले में अगर कोई दुकानदार नाबालिगों को तंबाकू बेच रहा है तो सब मिलकर आवाज उठाएँ। खुद व्यक्ति को भी एक बार रुककर सोचना होगा। जो सिगरेट आप आज पी रहे हैं, वो कल आपके बच्चे की आँखों में आसू बन सकती है। जो पैसा आप धुएँ में उड़ा रहे हैं, वो आपके घर की खुशहाली बन सकता है। तंबाकू छोड़ना आसान नहीं होता, पर असंभव भी नहीं। एक दिन में एक सिगरेट कम करें, अगले हफ्ते दो कम करें। डॉक्टर की सलाह लें, परिवार का साथ लें, और खुद से वादा करें कि अब और नहीं। हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने सालों की लत को तोड़कर नई जिंदगी शुरू की है। उनकी कहानियाँ बताती हैं कि अगर ठान लिया जाए तो आदत बदली जा सकती है। कुछ गाँवों और कस्बों ने दिखा दिया है कि सामूहिक संकल्प से क्या हो सकता है। यह पंचायतें तंबाकू से मुक्त गाँव का प्रस्ताव पास करती हैं, जब युवा मंडल घर-घर जाकर समझाते हैं, जब स्कूलों में बच्चे माता-पिता को शपथ



कठिन यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 : हिन्दी माध्यम की चुनौती

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की प्रारंभिक परीक्षा देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में गिनी जाती है। हर वर्ष लाखों छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन चयन कुछ हजार अभ्यर्थियों का ही हो पाता है। वर्ष 2026 का यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर विशेष रूप से चर्चा का विषय बना क्योंकि अधिकांश छात्रों और शिक्षकों ने इसे पिछले वर्षों की तुलना में अधिक कठिन, विरलषणात्मक और अप्रत्याशित बताया। इस कठिनाई ने केवल परीक्षा के परिणामों को ही प्रभावित नहीं किया, बल्कि छात्रों की मानसिक स्थिति, तैयारी की रणनीति और भविष्य की दिशा पर भी गहरा असर डाला है। विशेष रूप से हिन्दी माध्यम के छात्रों के सामने नई चुनौतियाँ और अधिक स्पष्ट होकर सामने आई हैं।

इस बार के प्रीलिम्स में सामान्य अध्ययन और सोसेट दोनों ही पेपरों का स्तर अपेक्षाकृत कठिन माना गया। प्रश्न सीधे तथ्यों पर आधारित होने के बजाय अवधारणात्मक, विश्लेषणात्मक और बहु-आयामी थे। कई प्रश्न ऐसे थे जिनमें विकल्प बहुत करीब थे, जिससे सही उत्तर चुनना कठिन हो गया। छात्रों का कहना था कि परीक्षा में केवल रटने वाली तैयारी से सफलता मिलना लगभग असंभव था। इससे उन छात्रों की अधिक परेशानी हुई जो पारंपरिक नोट्स और सीमित स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। कठिन पेपर का सबसे पहला असर छात्रों के आत्मविश्वास पर पड़ा। परीक्षा केंद्र से बाहर निकलते समय अधिकांश अभ्यर्थियों के चेहरों पर निराशा और असमंजस दिखाई दिया। कई छात्रों को यह समझ ही नहीं आया कि उन्होंने कितने प्रश्न सही किए हैं। यूपीएससी जैसी परीक्षा में अनिश्चितता पहले से ही बहुत अधिक होती है, लेकिन इस बार पेपर के स्तर ने उस मानसिक दबाव को और बढ़ा दिया। अनेक छात्रों ने सोशल मीडिया पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वर्षों की मेहनत के बाद भी पेपर इतना अप्रत्याशित था कि उन्हें अपनी तैयारी अधूरी लगने लगी। इस कठिनाई का दूसरा बड़ा प्रभाव कट-

ऑफ पर पड़ने वाला है। विशेषज्ञों का मानना है कि पेपर कठिन होने के कारण इस बार कट-ऑफ कम जा सकती है। हालांकि यह उन छात्रों के लिए राहत की बात हो सकती है जिन्होंने सीमित प्रश्नों का प्रयास किया लेकिन सटीकता बनाए रखी। दूसरी ओर, जिन छात्रों ने अधिक प्रश्न हल करने की रणनीति अपनाई थी, उन्हें नेगेटिव मार्किंग के कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस प्रकार कठिन पेपर ने छात्रों को यह सिखाया कि यूपीएससी में केवल अधिक प्रश्न करना ही सफलता की गारंटी नहीं है, बल्कि समझ और संतुलित रणनीति अधिक महत्वपूर्ण है।

कठिन प्रीलिम्स का असर केवल परीक्षा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य स्थिति को भी प्रभावित करता है। यूपीएससी की तैयारी करने वाले अनेक छात्र वर्षों तक सामाजिक जीवन से दूरी बनाकर पढ़ाई में लगे रहते हैं। जब परीक्षा अंकों से आर्थिक कठिन हो जाती है तो उनमें निराशा, तनाव और आत्म-संदेह बढ़ जाता है। कुछ छात्र अपनी क्षमता पर प्रश्न उठाने लगते हैं। कई बार यह मानसिक दबाव असंसाद तक का रूप ले लेता है। इसलिए विशेषज्ञ लगातार यह सलाह दे रहे हैं कि यूपीएससी की तैयारी को जीवन का अंतिम लक्ष्य न बनाकर एक अवसर

की तरह देखा जाना चाहिए। इस बार के कठिन पेपर ने कोचिंग संस्थानों और तैयारी के पैटर्न पर भी प्रश्न खड़े किए हैं। लंबे समय से यह धारणा बनी हुई थी कि सीमित कितानों और नोट्स से यूपीएससी प्रीलिम्स आसानी से निकाला जा सकता है।

लेकिन इस बार के प्रश्नों ने स्पष्ट कर दिया कि आयोग अब केवल तथ्य याद करने वाले छात्रों के बजाय गहरी समझ और विश्लेषणात्मक सोच रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देना चाहता है। इसका अर्थ है कि आने वाले वर्षों में छात्रों को अखबार, सरकारी रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय घटनाओं और अवधारणात्मक समझ पर अधिक ध्यान देना होगा।

विशाल कल्याण

यदि हिन्दी माध्यम के छात्रों की बात करें तो इस कठिन पेपर का प्रभाव उन पर अपेक्षाकृत अधिक देखने को मिल सकता है। पिछले कुछ वर्षों से ही हिन्दी माध्यम के छात्रों का चयन अनुपात लगातार घट रहा है। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं, जिनमें गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री की कमी, अनुवाद की समस्याएँ और सीमित मार्गदर्शन प्रमुख हैं। इस बार के कठिन और विश्लेषणात्मक प्रश्नों ने इन चुनौतियों को और अधिक उजागर कर दिया।

हिन्दी माध्यम के कई छात्रों ने शिकायत की कि प्रश्नों का हिन्दी अनुवाद जटिल और भ्रमित करने वाला था। यूपीएससी के प्रश्नपत्रों में अक्सर अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद किया जाता है, लेकिन कई बार तकनीकी शब्दों और अवधारणाओं का अनुवाद स्वाभाविक नहीं होता। इससे छात्र प्रश्न का वास्तविक अर्थ समझने में समय गंवा देते हैं। कठिन पेपर में जहाँ हर मिनट महत्वपूर्ण होता है, वहाँ भाषा संबंधी यह समस्या बड़ी चुनौती बन जाती है।

इसके अलावा हिन्दी माध्यम के छात्रों के पास उच्च गुणवत्ता वाली समाचारिक सामग्री और टेस्ट सीरीज की भी सीमित उपलब्धता होती है। अधिकांश श्रेष्ठ सामग्री पहले अंग्रेजी में उपलब्ध होती है और बाद में उसका अनुवाद किया जाता है। कई बार अनुवाद में भाव और संदर्भ बदल जाते हैं। परिणामस्वरूप हिन्दी माध्यम के छात्र अवधारणात्मक तैयारी में पीछे रह जाते हैं। इस बार के पेपर में चूँकि प्रश्न सीधे तथ्यों के बजाय विश्लेषण पर आधारित थे, इसलिए यह अंतर और स्पष्ट दिखाई दिया। डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन शिक्षा के विस्तार के बावजूद हिन्दी माध्यम के छात्रों को समान अवसर अभी भी पूरी तरह नहीं मिल पाए हैं। यद्युक्त, टेलीग्राम और अन्य ऑनलाइन माध्यमों पर सामग्री उपलब्ध तो है, लेकिन

उसकी गुणवत्ता में काफी अंतर होता है। अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्रोतों तक सीधी पहुँच मिल जाती है, जबकि हिन्दी माध्यम के छात्र अक्सर सीमित और संक्षिप्त सामग्री पर निर्भर रह जाते हैं। कठिन पेपर में यह सीमितता नुकसान का कारण बन सकती है।

हालांकि यह भी सत्य है कि कठिन पेपर सभी छात्रों के लिए समान चुनौती लेकर आता है। यदि परीक्षा कठिन होती है तो कट-ऑफ भी उसी अनुपात में घटती है। ऐसे में जिन हिन्दी माध्यम के छात्रों ने मजबूत अवधारणात्मक तैयारी की है, उनके लिए अवसर भी बन सकते हैं। यूपीएससी अंततः वही छात्र चुनता है जो धैर्य, निरंतरता और समझ के साथ तैयारी करता है। इसलिए केवल भाषा को असफलता का कारण मानना उचित नहीं होगा, बल्कि तैयारी की गुणवत्ता और रणनीति पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

इस बार के प्रीलिम्स ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि यूपीएससी अब पारंपरिक तैयारी के ढाँचे से आगे बढ़ चुका है। केवल कोचिंग नोट्स और तथ्य याद करना पर्याप्त नहीं है। छात्रों को बहुआयामी अध्ययन, समाचारिक घटनाओं की गहरी समझ और तार्किक सोच विकसित करनी होगी। हिन्दी माध्यम के छात्रों के लिए यह समय आत्मविश्वास खोने का नहीं बल्कि अपनी तैयारी के तरीके को आधुनिक और व्यापक बनाने का है।

सरकार और आयोग को भी इस दिशा में गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है। प्रश्नपत्रों के बेहतर अनुवाद, गुणवत्तापूर्ण हिन्दी सामग्री की उपलब्धता और क्षेत्रीय भाषाओं में समान अवसर सुनिश्चित करना आवश्यक है। यदि देश के ग्रामीण और हिन्दी भाषी क्षेत्रों के प्रतिभाशाली युवाओं को समान संसाधन मिलें, तो वे भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। अंततः कहा जा सकता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का कठिन पेपर केवल एक परीक्षा नहीं बल्कि भारतीय प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली के बदलते स्वरूप का संकेत है। इसने छात्रों को यह समझाया है कि सफलता केवल मेहनत से नहीं बल्कि सही दिशा में की गई समझदार मेहनत से मिलती है। हिन्दी माध्यम के छात्रों के लिए यह चुनौती अवश्य है, लेकिन यह अवसर भी है कि वे नई रणनीतियों, बेहतर संसाधनों और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। कठिन परीक्षाएँ हमेशा मजबूत उम्मीदवारों को तैयार करती हैं, और यही इस बार के प्रीलिम्स का सबसे बड़ा संदेश है।

साभार
विशाल कल्याण
सहायक प्रोफेस

कर्नाटक में बदलाव के बाद की चुनौतियाँ

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धमैया के त्यागपत्र देने के साथ ही उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के राज्य की कमान संभालने का रास्ता साफ हो गया। इससे शिवकुमार की तो चाहत पूरी हो गई, लेकिन यह कहना कठिन है कि कर्नाटक कांग्रेस में सब कुछ सामान्य होने जा रहा है या फिर राज्य की विभिन्न समस्याओं के समाधान की राह आसान हो गई है। सिद्धमैया ने त्यागपत्र देने की घोषणा करते हुए यह कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने जैसा कहा, मैंने वैसा किया, लेकिन उन्होंने राज्यसभा आकर कांग्रेस की केंद्रीय स्तर की राजनीति में सक्रिय होने का आग्रह टुकड़ते हुए कहा कि वे राज्य की राजनीति में ही सक्रिय रहेंगे। चूँकि सिद्धमैया जमीनी स्तर की राजनीति करने वाले नेता हैं और उनका अपना जनाधार है, इसलिए वे उपमुख्यमंत्री बनने जा रहे शिवकुमार के लिए चुनौती खड़ी कर सकते हैं। इसके नतीजे में वहाँ नए सिरे से गुटबाजी भी पनप सकती है, क्योंकि शिवकुमार के नेतृत्व वाली सरकार के मंत्रिमंडल से सिद्धमैया के कुछ समर्थक बाहर हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह स्वाभाविक ही है कि शिवकुमार अपने हिसाब से शासन से चलाएँगे और इसके लिए वे प्रशासन में भी पूर्व मुख्यमंत्री के समर्थकों को किनारे कर सकते हैं। इसके आसरा कम ही है कि सिद्धमैया अपने उत्तराधिकारी शिवकुमार के लिए खुला मैदान छोड़ेंगे, क्योंकि जमीनी राजनीति करने वाला कोई नेता अपना राजनीतिक वर्चस्व इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। अपने देश में तो ऐसा और भी कम होता है। अपने यहाँ उग्रद्वारा नेता तब तक राजनीति से रिटायर नहीं होते, जब तक उन्हें बिल्कुल किनारे न कर दिया जाए। कांग्रेस सिद्धमैया की उपेक्षा करने का जोखिम नहीं उठा सकती। शिवकुमार 2023 में तभी से उपमुख्यमंत्री पद के आकांक्षी थे, जब कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव जीता था, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने वरिष्ठता के आधार पर सिद्धमैया का चयन किया। शिवकुमार का दावा था कि उनके लिए सिद्धमैया के बीच इसे लेकर सहमति कायम हुई थी कि दोनों ढाई-ढाई वर्ष तक सत्ता संभालेंगे। अपने इन दावे के अनुरूप वे पिछले

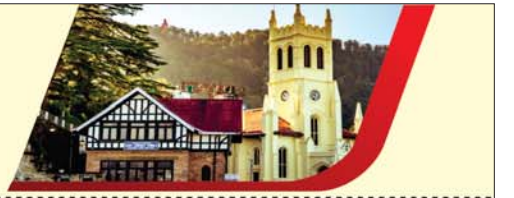


काफी समय से मुख्यमंत्री पद हासिल करने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन सिद्धमैया पद छोड़ने को तैयार नहीं थे। आखिरकार कांग्रेस आलाकमान के दबाव में वे तीन वर्ष बाद मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार हुए। स्पष्ट है कि उन्होंने मजबूरी में पद छोड़ा।

कर्नाटक की तरह एक समय राजस्थान में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच भी इसे लेकर खींचतान हुई थी कि दोनों के बीच ढाई-ढाई साल तक मुख्यमंत्री बनने की सहमति बनी थी। सचिन पायलट ने बहुत कोशिश की कि इस कथित सहमति के आधार पर उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिले, लेकिन अशोक गहलोत टय से मस नहीं हुए। उन्होंने कांग्रेस आलाकमान के निर्देशों को भी टुकरा दिया। इस कारण सचिन पायलट एवं उनके बीच खींचतान जारी रही और कांग्रेस आलाकमान अंत समय तक कोई फैसला नहीं कर सका। ऐसा ही छत्तीसगढ़ में हुआ।

यहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएस सिंह देव के बीच इसे लेकर झगड़ा होता रहा कि ढाई-ढाई साल तक सत्ता संभालने की बात हुई थी। यहाँ भी कांग्रेस नेतृत्व कोई फैसला नहीं कर सका। नतीजा यह हुआ कि इन दोनों राय्यों में कांग्रेस की पराजय का एक कारण मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए खींचतान भी बनी। कांग्रेस नेतृत्व ने पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को विधानसभा चुनाव के करीब एक वर्ष पहले मुख्यमंत्री से हटाने के लिए बाध्य किया, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू उनके खिलाफ खड़े हो गए थे। हालांकि मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके बजाय चरणजीत सिंह चड्डी को मिली। इसके चलते गुटबाजी को बढ़ावा मिला और विधानसभा चुनावों में इसका लाभ

आम नादमी पार्टी ने उठाया। कर्नाटक में दो वर्ष बाद चुनाव होने हैं। कहना कठिन है कि तब क्या होगा, लेकिन यह ध्यान रहे कि कर्नाटक में 1980 के बाद कोई भी सरकार सत्ता में नहीं लौटी है। शिवकुमार इस सिलसिले को तोड़ सकेंगे, यह कहना इसलिए कठिन है, क्योंकि कर्नाटक कई समस्याओं से घिरा है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु आइटी सिटी के रूप में विख्यात है, लेकिन इस समय बेंगलुरु के साथ देश भर का आइटी उद्योग समस्याओं से घिरा है। कर्नाटक में बेंगलुरु को छोड़कर एक दो शहर ही सही तरह विकसित हो पाए हैं। बेंगलुरु और शेष राज्य में जो आर्थिक असमानता दिखती है, वह यही बताती है कि सरकारों ने अन्य शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। कर्नाटक उसी तरह की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं से जूझ रहा है, जैसे अन्य कई राज्य। किसी भी दल के लिए कर्नाटक के लोगों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना इसलिए कठिन होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र को जनता को संतुष्टि के नाम पर विकास के काम कम, लोकलुभावय योजनाओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है। यह किसी से छिपा नहीं कि रेवड़ी राजनीति कर्नाटक के लिए एक समस्या बन गई है। लोकलुभावय योजनाओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है। यह किसी से छिपा नहीं कि रेवड़ी राजनीति कर्नाटक के लिए एक समस्या बन गई है। फेर में राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है। ऐसी योजनाओं से एक तो मुप्तखोरी की संस्कृति पनपती है और दूसरे राज्य की वित्तीय सेहत बिगड़ती है। ऐसा कुछ अन्य राज्यों में भी हो रहा है। कर्नाटक की तरह कई राज्यों में आर्थिक विकास राजधानी और चुनिंदा शहरों में ही केंद्रित दिखाता है।



संक्षिप्त न्यूज

थानाकला स्कूल में तम्बाकू निषेध एवं पर्यावरण दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को किया सम्मानित



बंगणा, (जोगिंद्र देव आर्य) राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला थानाकला में तम्बाकू निषेध दिवस और पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया गया। जिसमें गरिमा कक्षा बारहवीं प्रथम स्थान, मीनाक्षी द्वितीय स्थान तथा किंजल तृतीय स्थान पर रहीं जिनको पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। सभी को विश्व पर्यावरण दिवस के (5 जून) बारे में भी जानकारी बांटी गई। प्रधानाचार्य संजीव पराशर ने विद्यार्थियों को पेड़ लगाने, जंगलों को आग से बचाने, प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करने तथा अपने आसपास स्वच्छता रखने के बारे में प्रेरित किया गया। इस मौके पर स्थानीय पाठशाला से हंसराज, नंदलाल, हरिन्द्र देव, लवेश विनोद, किरण, रेखा, रजनीश शर्मा, राकेश शर्मा, संदेश, राधिका, आशा आदि समस्त स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे।

विश्व तंबाकू दिवस पर पेंटिंग, निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित



बिलासपुर (जितेंद्र गौतम) - राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मजारी में 31 मई को छुट्टी होने के कारण राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मजारी में विश्व तंबाकू दिवस को 30 मई को ही मनाने का फैसला विद्यालय प्रशासन द्वारा लिया गया

निश्चित विश्व तंबाकू दिवस मनाने के उद्देश्य पर श्री मति रेखा अत्री ने अपने विचार रखते हुए बताया कि बाजार में कई उत्पाद तंबाकू के बने हुए विक्री किए जाते हैं, उनके दुष्परिणामों को भी उसी पैकेट पर दर्शाया गया होता है, परंतु उसे अनदेखा कर इसका सेवन लोग करते हैं और कई प्रकार की बीमारियों से सेवनधारी ग्रसित हो जाते हैं अतः बच्चों को इस प्रकार के उत्पादों से दूर रहकर समाज में जागरूकता फैलानी चाहिए

इस अवसर पर बच्चों ने नारा लेखन, पेंटिंग निबंध लेखन प्रतियोगिता में भाग लेकर अपनी जानकारी को अध्यापकों के समक्ष रखा, प्रधानाचार्य सुरजीत सिंह ने बच्चों को इस समस्या को जानने समझने की जिज्ञासा को प्रशंसा की और बताया कि हिमाचल सरकार ने नशे पर लगाम कसने की कई योजनाएं बनाई हैं जिससे हमारे स्कूली बच्चों को इस बीमारी से बचाया जा सके, परंतु अफसोस सरकार के प्रयत्नों के बावजूद ये बीमारी फैलती जा रही है हम सभी को एकजुटता से इसके विरुद्ध खड़े होना पड़ेगा

प्रधानाचार्य ने बच्चों द्वारा तंबाकू निषेध का संदेश देने के लिए बनाई पेंटिंग, लिखे गए नारे और निबंध का निरीक्षण कर बच्चों और अध्यापकों के कार्य की सराहना की

इस अवसर पर श्री मति अनुराधा शर्मा, हरप्रीत कौर, रेखा अत्री, सतनाम कौर, रेणु शर्मा, सुमन ठाकुर, शीला, दर्शना सहित सारा स्टाफ उपस्थित रहा।

द मैक्स अकादमी में सात दिवसीय भारतीय भाषा कैम्प का आयोजन इस वर्ष पंजाबी भाषा से परिचित कराया



बीबीएन, 30 मई (तारा) - बड़ी के धर्मपुर स्थित द मैक्स अकादमी स्कूल में सात दिवसीय भारतीय भाषा कैम्प का आयोजन किया गया, जिसमें इस वर्ष पंजाबी भाषा को विशेष रूप से चुना गया। कैम्प का उद्देश्य विद्यार्थियों को पंजाबी भाषा, संस्कृति एवं परंपराओं से परिचित कराना था। स्कूल की शिक्षिका मुस्कान ने बताया कि कैम्प के दौरान विद्यार्थियों को पंजाबी भाषा की मूल जानकारी, अभिवादन, वर्णमाला, बोलचाल एवं संस्कृति से जुड़ी अनेक रोचक गतिविधियाँ सिखाई गईं। बच्चों ने पूरे उत्साह एवं रुचि के साथ सभी गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग लिया। विद्यालय की ओर से विद्यार्थियों को पुरस्कार सहित का भ्रमण भी करवाया गया, जहाँ बच्चों ने सेवा भावना एवं सिख परंपराओं के बारे में जाना। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों ने पंजाबी लोक नृत्य गिड्डा एवं भांगड़ा सीखा। बच्चों को पंजाबी कढ़ाई कला तथा पारंपरिक खेलों की जानकारी भी दी गई। कैम्प के अंतिम दिन लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने मिलकर सेवा भाव से भोजन तैयार किया और सभी को परोसा। इस अवसर पर विद्यालय का वातावरण पंजाबी संस्कृति के रंगों से सराबोर दिखाई दिया।

पंचायत चुनावों में जनता ने सुनाया सरकार के खिलाफ जनादेश : जयराम ठाकुर

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने गृह पंचायत मुरहाग में किया मतदान, कहा, सरकार ने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हुए कई तरह के षडयंत्र और प्रलोभन वाले हथकंडे अपनाए

» प्रथम न्यूज । मंडी
30 मई (एएम नाथ)

पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पंचायतीराज चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण में शनिवार को मंडी जिला के अंतर्गत अपने सराज विधानसभा क्षेत्र को गृह पंचायत मुरहाग के मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया और इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी सक्रिय सहभागिता निभाते हुए प्रदेश के सभी मतदाताओं से सुशासन, पारदर्शी प्रशासन और ग्रामीण विकास के लिए योग्य प्रतिनिधियों को चुनने का आग्रह किया।

बाद उन्होंने सराज विधानसभा की ही ग्राम पंचायत तुंगाधार की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी से घर में आत्मीय भेंट कर उन्हें नवीन दायित्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं और विश्वास व्यक्त किया कि सभी नवनिर्वाचित प्रतिनिधि जनहित को सर्वोपरि रखते हुए पंचायतों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित भाव से कार्य करेंगे।

इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होने पर जनता का आभार जताते हुए कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर तीखा राजनीतिक हमला बोला और आरोप लगाया कि ये चुनाव पिछले साल दिसंबर में ही हो जाने चाहिए थे लेकिन कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर आपदा का बहाना बनाकर इन्हें छह महीने आगे खिसका दिया क्योंकि सरकार की शुरु से ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सामना करने की मंशा नहीं थी, जिसके खिलाफ भाजपा को हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी और अंततः देश की शीर्ष अदालत के कड़े आदेशों के बाद ही राज्य चुनाव आयोग ने इन चुनावों की प्रक्रिया शुरू की, जिसके



प्रत्युत्तर में सुक्खू सरकार ने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हुए कई तरह के षडयंत्र और प्रलोभन वाले हथकंडे अपनाए लेकिन प्रदेश की रोकने वाली कार्यप्रणाली से पूरी तरह तंग आ चुकी है और आने वाले समय में प्रदेश की सत्ता में पुनः भारतीय जनता पार्टी को वापस लाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है, क्योंकि सत्ता के इस सेमीफाइनल माने जाने वाले पंचायती चुनाव में भाजपा ने जो प्रचंड बढ़त बनाई है वह सुक्खू सरकार की आंखें खोलने के लिए काफी

है जबकि मुख्यमंत्री अपनी साख बचाने के लिए लगातार झूठ का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकास को ठप करने वाली इस जनविरोधी कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अब प्रदेश की जनता पूरी तरह कमर कस चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने ये कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनादेश दिया है जिसे सरकार को स्वीकार करना चाहिए।

ईडी द्वारा गिरफ्तार जैक एकेडमी संचालकों

से क्या रिश्ता बताएँ मुख्यमंत्री सुक्खू...?

नेता प्रतिपक्ष ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कार्यप्रणाली और संदिग्ध व्यावसायिक सल्लसता पर अत्यंत गंभीर सवाल उठाए हैं कि चंडीगढ़, मोहाली, जीरकपुर और पंजाब के रियल एस्टेट क्षेत्र में मनी लॉन्ड्रिंग और घर खरीदारों के करोड़ों रुपये की हेराफेरी के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किए गए संचालकों और प्रदेश में चल रही %क्रेक एकेडमी% से संबंधित प्रमोटर्स से आखिर मुख्यमंत्री का क्या गुप्त रिश्ता है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने स्वयं प्रदेश विधानसभा के भीतर बड़े-बड़े वादे करते हुए सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि यह %क्रेक एकेडमी% हिमाचल प्रदेश के हर एक विधानसभा क्षेत्र में अपनी शाखाएं खोलेंगे जिसके प्रचार-प्रसार और तथाकथित कौशल विकास के नाम पर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपये फूंक दिए गए लेकिन आज जब ईडी की जांच में इन प्रमोटर्स द्वारा घर खरीदारों के पैसों को शेल कंपनियों और अंतर्निहित संदेहास्पद वित्तीय लेन-देन के नेटवर्क के माध्यम से डायवर्ट करने तथा सीएलएयू मंजूरीयों में भारी हेराफेरी और विनियामक मानदंडों के उल्लंघन की संदिग्ध भूमिका पाई गई है और मुख्य आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है, तो यह हिमाचल प्रदेश के युवाओं और सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग का एक बहुत बड़ा घोटाला प्रतीत होता है जिसने मुख्यमंत्री कार्यालय की शुचितता को पूरी तरह कदमर्से में खड़ा कर दिया है, इसलिए मुख्यमंत्री को तुरंत प्रदेश की जनता के सामने आकर यह स्पष्ट करना चाहिए कि इन दागों और हवाला कारोबार में सल्लस प्रमोटर्स को संरक्षण देने के पीछे उनकी क्या मजबूरी थी।

उपायुक्त ने विभिन्न मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण, वरिष्ठ मतदाताओं से भी की बातचीत

तीसरे चरण में जिला की 58 ग्राम पंचायतों में शांतिपूर्ण सम्पन्न हुआ मतदान



» प्रथम न्यूज । बिलासपुर
30 मई (जितेंद्र गौतम)

जिला बिलासपुर में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के तृतीय एवं अंतिम चरण में आज 58 ग्राम पंचायतों में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। मतदान प्रक्रिया के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त राहुल कुमार ने नौगाँ, कल्लर और कंदरौरी ग्राम पंचायतों के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त ओम कांत ठाकुर भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त

ने मतदान केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्थाओं तथा मतदान उपरान्त होने वाली मतगणना के लिए किए गए प्रबंधों का भी जायजा लिया। उन्होंने बिजली आपूर्ति, बैटरी बैकअप, बैकल्पिक प्रकाश व्यवस्था और अन्य आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता की भी समीक्षा की। इस बीच उपायुक्त ने विभिन्न मतदान केंद्रों पर पहुंचे वरिष्ठ मतदाताओं से भी बातचीत कर उनके अनुभव जाने और मतदान प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रतिकूल मौसम के बावजूद मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला, जो लोकतांत्रिक मूल्यों



के प्रति लोगों की आस्था को दर्शाता है। यही नहीं खराब मौसम और वर्षा के किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए दिनभर सक्रिय रहा। मतदान केंद्रों तक मतदाताओं की सुगम पहुंच सुनिश्चित करने तथा मतदान एवं मतगणना प्रक्रिया के निर्बाध संचालन के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी लगातार फील्ड में तैनात रहे। जिला के विभिन्न क्षेत्रों में लोक निर्माण, विद्युत, जल शक्ति तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने ग्राउंड ज़ीरो पर रहकर व्यवस्थाओं को निगरानी की। प्रशासन

का प्रयास रहा कि मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक पहुंचने और मताधिकार का प्रयोग करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। राहुल कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना रहा कि मौसम की चुनौतियों के बावजूद किसी भी मतदाता को मतदान केंद्र तक पहुंचने अथवा मतदान प्रक्रिया में भाग लेने में कोई परेशानी न हो। इसके लिए सभी संबंधित विभागों को पहले से सतर्क रखा गया और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्रवाई के लिए टीमें फील्ड में तैनात रहीं।



वर्षा व खराब मौसम के बावजूद मतदाताओं ने बढ़-चढ़ कर मतदान में लिया भाग

बिलासपुर, 30 मई (जितेंद्र गौतम) - जिला बिलासपुर में पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे और अंतिम चरण में वर्षा और खराब मौसम के बावजूद मतदाताओं ने बढ़-चढ़ कर मतदान में भाग लिया। सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की लंबी-लंबी कतारें देखने को मिली। लोकतंत्र के इस पर्व में बुजुर्गों के साथ-साथ युवाओं तथा महिलाओं ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित बनाई।

जिला में तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव में आज ग्राम पंचायत पनौल की 101 वर्षीय नगरजु देवी, 98 वर्षीय निकी देवी, 90 वर्षीय विद्या देवी, निहातु देवी, ग्राम पंचायत कंदरौरी की 98 वर्षीय विमला देवी, ग्राम पंचायत कल्लर के 91 वर्षीय दुर्गा राम, सुहनु की 95 वर्षीय हरि देवी सहित अन्य वरिष्ठ नागरिकों ने मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान में भाग लिया। इसी बीच ग्राम पंचायत बकरोआ की 21 वर्षीय पारूल, 22 वर्षीय वंशिका ने पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। यही नहीं मतदान में जिला भर में महिला मतदाताओं की भागीदारी भी सराहनीय रही।

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने वरिष्ठ नागरिकों के हौसले की सराहना करते हुए कहा कि लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदारी सुनिश्चित बनाने के लिए ने केवल वे मतदान केंद्र तक पहुंचे बल्कि दूसरे मतदाताओं को प्रेरित करने का भी कार्य किया। उन्होंने युवा तथा महिला मतदाताओं की बड़ी तादाद में भागीदारी की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मतदान के माध्यम से सामूहिक भागीदारी से न केवल हमारा लोकतांत्रिक ढांचा ज्यदा सुदृढ़ एवं मजबूत बनता है बल्कि गांव, प्रदेश व देश के विकास में एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव कर नागरिक राष्ट्र निर्माण में भी अहम भूमिका निभाते हैं।

महिला कर्मचारी ने लगाए गंभीर आरोप, निष्पक्ष जांच की उठी मांग

» प्रथम न्यूज । सोलन
30 मई (एएम नाथ)

सोलन में एक बैंक की महिला कर्मचारी द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और संस्थागत जवाबदेही को लेकर नई बहस खेड़ दी है। महिला कर्मचारी निशा ठाकुर ने बैंक के कुछ अधिकारियों और प्रबंधन पर मानसिक उत्पीड़न, अनावश्यक निगरानी और उनके खिलाफ सुनियोजित माहौल तैयार करने के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कुछ वरिष्ठ अधिकारियों और प्रबंधन के बीच कथित मिलीभगत के कारण उन्हें लगातार मानसिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है।

महिला कर्मचारी के आरोप सामने आने के बाद यह मामला चर्चा का विषय बन गया है। कर्मचारी वर्ग, सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों का कहना है कि किसी भी महिला कर्मचारी द्वारा बार-बार अपनी सुरक्षा, सम्मान और कार्यस्थल के माहौल को लेकर चिंता व्यक्त करना गंभीर विषय है, जिसे

नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनका मानना है कि मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच कराई जानी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई हो। विशेषज्ञों के अनुसार प्रत्येक संस्थान की ज़िम्मेदारी है कि वह अपने कर्मचारियों, विशेषकर महिला कर्मचारियों, को सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण उपलब्ध कराए। यदि किसी कर्मचारी को उत्पीड़न, दबाव या असुरक्षा की भावना का सामना करना पड़ रहा है, तो शिकायत निवारण तंत्र को सक्रिय और प्रभावी ढंग से कार्य करना चाहिए। हालांकि, आरोपों की अभी तक स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित अधिकारियों की ओर से विस्तृत प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है। ऐसे में निष्पक्ष जांच ही इस मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट कर सकती है। लोगों का कहना है कि पारदर्शिता, जवाबदेही और न्यायपूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से ही संस्थागत विश्वास को बनाए रखा जा सकता है।

पीएम श्री राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नालागढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान

» प्रथम न्यूज । बीबीएन
30 मई (तारा)

पीएम श्री राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नालागढ़ (जिला सोलन) के लिए यह अत्यंत गर्व और सम्मान का क्षण है कि विद्यालय को नई दिल्ली में आयोजित स्कूल चैलेंज-टॉफेल 2025 के राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में बेस्ट परफॉर्मिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि पूरे प्रदेश का यह एकमात्र विद्यालय रहा जिसे राष्ट्रीय स्तर पर यह पुरस्कार प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। यह प्रतिष्ठित सम्मान विद्यालय के सभी होनहार छात्रों, अध्यापकों, एंटी ड्यू क्लब की नोडल अधिकारी सुमन बाला के अथक प्रयासों, मेहनत एवं समर्पण तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य मनोज कुमार के कुशल मार्गदर्शन का परिणाम है। विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों



एवं समाज में नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु लगातार विभिन्न गतिविधियों, जागरूकता अभियान, रैलियाँ एवं प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती रही हैं। राष्ट्रीय स्तर के इस सम्मान समारोह में भाग लेने के लिए विद्यालय की ओर से राज्य स्तर पर वर्षा सूद (राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी- एंटी ड्यू क्लब) एवं

नोडल अधिकारी सुमन बाला ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान पूरे विद्यालय परिवार के सामूहिक प्रयासों का प्रतिफल है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह उपलब्धि बीबीएन क्षेत्र में नशा विरोधी जागरूकता अभियान को और अधिक सशक्त बनाएगी तथा समाज को नशा मुक्त बनाने की दिशा में प्रेरित करेगी। विद्यालय के प्रधानाचार्य मनोज कुमार ने इस उपलब्धि पर सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं स्टाफ सदस्यों को हार्दिक बधाई दी है।

विद्यालय से सुमन बाला (हिन्दी प्रवक्ता (नोडल अधिकारी- एंटी ड्यू क्लब) * तथा मृगाल (कंप्यूटर अध्यापिका) नई दिल्ली गए थे और उन्होंने विद्यालय का प्रतिनिधित्व किया। विद्यालय की एंटी-ड्यू क्लब की





एशियन गेम्स ट्रायल के सेमीफाइनल में हारीं विनेश फोगाट

उभरती पहलवान मीनाक्षी गोयत ने दी शिकस्त

दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में चल रहे एशियाई खेलों (Asian Games) के चयन ट्रायल से एक बेहद हैरान करने वाली और बड़ी खेल खबर सामने आ रही है। देश की स्तर और अनुभवी महिला पहलवान विनेश फोगाट को महिलाओं के 53 किलोग्राम भारवर्ग के एक कड़े मुकाबले में करारी हार का सामना करना पड़ा है। इस बेहद रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले में भारत की उभरती हुई युवा पहलवान मीनाक्षी गोयत ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए दिग्गज विनेश फोगाट को 6-4 से शिकस्त देकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। इस उलटफेर के बाद विनेश फोगाट के एशियाई खेलों में सीधे चयन के सपनों को बड़ा झटका लगा है।



गेम्स सिलेक्शन ट्रायल्स में विनेश फोगाट ने अपनी शुरुआत बेहद आक्रामक और धमाकेदार अंदाज में की थी। उन्होंने शुरुआती दो मुकाबले जीतकर अपनी वापसी की उम्मीदों को पूरी तरह जिंदा रखा था। 53 किग्रा कैटेगरी के अपने पहले राउंड के मुकाबले में विनेश फोगाट ने हरियाणा की ज्योति को 7-1 के बड़े

अंतर से आसानी से धूल चटाई थी। इसके बाद हुए दूसरे कड़े मुकाबले में उनका सामना निशु से हुआ। यह मुकाबला बेहद हार्ड-वॉल्टेज और ड्रामे से भरपूर रहा। मैच खत्म होने तक दोनों पहलवानों का स्कोर 6-6 से पूरी तरह बराबर रहा था, लेकिन तकनीकी मानदंडों के आधार पर विनेश फोगाट को विजेता

घोषित कर आगे बढ़ा दिया गया। इस मैच के आखिरी क्षणों में निशु ने एक शानदार 'टेक ड्रॉउन' का प्रयास किया था, लेकिन रेफरी द्वारा उन्हें अंक नहीं दिए गए। फेसले से असहमत निशु के कोच ने तुरंत इस निर्णय को चुनौती (चैलेंज) दी, लेकिन रिज्यू के बाद भी वे यह चैलेंज हार गए और विनेश फोगाट

ने राहत की सांस ली। इस विवादास्पद फेसले से पूरी तरह स्तब्ध और निराश होकर निशु ने खेल भावना के विपरीत रेफरी और विनेश फोगाट से हाथ मिलाने तक से इनकार कर दिया था और काफी देर तक मैच पर ही भावुक होकर खड़ी रही थीं।

सेमीफाइनल में मीनाक्षी गोयत ने पलटा पासा

दो बेहद थका देने वाले मुकाबले जीतने के बाद विनेश फोगाट जब सेमीफाइनल के मैच पर उतरीं, तो युवा पहलवान मीनाक्षी गोयत ने उनके अनुभव पर अपनी फुर्ती और बेहतरीन तकनीक को हावी कर दिया। मीनाक्षी ने मुकाबले की शुरुआत से ही विनेश पर दबाव बनाए रखा और डिफेंसिव खेल के साथ-साथ सटीक अटैक किए।

विनेश फोगाट ने मैच में वापसी की कई कोशिशें कीं, लेकिन मीनाक्षी गोयत ने उन्हें ज्यादा मौके नहीं दिए और अंततः 6-4 के स्कोर से मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही मीनाक्षी ने फाइनल का टिकट कटा लिया है, जबकि विनेश फोगाट की इस अप्रत्याशित हार ने कुश्ती के जानकारों और उनके फैंस को हैरान कर दिया है।



फाइनल में आखिर कौन किस पर पड़ेगा भारी? आंकड़ों के लिहाज से मिल रहे चैंपियन के संकेत

गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आईपीएल 2026 का फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेला जाएगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। आरसीबी अपने खिताब की रक्षा करने उतरेगी। याद दिला दें कि आरसीबी ने आईपीएल 2026 के पहले क्वालीफायर में जीटी को 92 रन से मात देकर फाइनल में प्रवेश किया था। फिर गुजरात ने दूसरे क्वालीफायर में राजस्थान रॉयल्स को सात विकेट से मात देकर फाइनल में एंटी की। गुजरात ने शुक्रवार को दूसरे क्वालीफायर में अपने आईपीएल के सबसे बड़े लक्ष्य का सफल पीछ करके फाइनल में प्रवेश किया।

दोनों टीमों के बीच आंकड़ों पर गौर करें तो काफी करीबी मुकाबला है, जिससे पता लगा पाना मुश्किल है कि चैंपियन कौन बनेगा। आरसीबी और गुजरात के बीच अब तक कुल 9 मैच खेले गए हैं। आरसीबी ने 5 जीते जबकि गुजरात ने 4 मैच अपने नाम किए। फाइनल में आरसीबी इस अंतर को बढ़ाना चाहेगा जबकि गुजरात हिसाब बराबर करके खिताब अपने नाम करने का प्रयास करेगा। आईपीएल 2026 में दोनों टीमों 3 बार आमने-सामने आईं। इसमें आरसीबी 2-1 से आगे है।

किंग और प्रिंस की जंग

अब गुजरात अपने होमग्राउंड पर घरेलू फैंस के सामने खिताब जीतने की कोशिश करेगा। मगर उसके लिए यह आसान नहीं होगा क्योंकि आरसीबी गुजब के फॉर्म में है। दोनों ही टीमों के पास दूसरा आईपीएल खिताब जीतने का मौका है। जीटी ने 2022 में पहली बार खिताब जीता था। आरसीबी ने 2025 में 18 साल का सूखा खत्म करके खिताब अपने नाम किया।

आंकड़ों किस्का दे रहे साथ गुजरात और बेंगलुरु के बीच आईपीएल 2026 फाइनल बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। दोनों ही टीमों में जबर्दस्त फॉर्म के साथ फाइनल खेलने पहुंच रही हैं। ऐसे में दोनों ही टीमों हर उस पहलु पर गौर करेंगी, जिससे उन्हें मनोवैज्ञानिक लाभ मिल सके।

आरसीबी और जीटी के बीच मैच के साथ-साथ विराट कोहली और शुभमन गिल के बीच भी एक मजेदार मुकाबला देखने को मिलेगा। दोनों की कोशिश बेहतरीन पारी खेलकर अपनी टीम को चैंपियन बनाने की होगी। आरसीबी और जीटी के गेंदबाजी आक्रमण के बीच भी मजबूत टक्कर देखने को मिलेगी।



डराने वाले हैं विराट कोहली के आईपीएल फाइनल में आंकड़े, आरसीबी के लिए ही न परेशानी बन जाएं किंग

मौजूदा विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) अपना खिताब बचाने के करीब है। रजत पाटीदार की कप्तानी वाली इस टीम ने फाइनल में जगह बना ली है। खिताबी मुकाबले में उसका सामना रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस से होगा। इस मैच में सभी की नजरें विराट कोहली पर रहेंगी जो अपना पांचवां आईपीएल फाइनल खेलने जा रहे हैं।



फाइनल में शांत रहा है बल्लर कोहली ने अभी तक चार फाइनल खेले हैं और पांचवां आईपीएल खेलने जा रहे हैं। चार आईपीएल

फाइनल में उन्होंने मिलकर 140 रन बनाए हैं। जिसमें से सिर्फ एक मैच में ही उन्होंने अर्धशतक जमाया है। कोहली ने पहला आईपीएल फाइनल अनिल कुंबले को कप्तानी में साल 2009 में डेक्कन चाजर्स के खिलाफ खेला था जिसमें आठ गेंदों पर सात रन ही बनाए थे। 2011 में आरसीबी ने फिर फाइनल खेला और इस बार चेन्नई सुपर किंग्स उसके सामने थी। इस मैच में कोहली के बल्ले से 32 गेंदों पर 35 रन बनाए।

2016 में आरसीबी ने अपना तीसरा फाइनल खेला। ये फाइनल उसने कोहली की कप्तानी में ही खेला। ये वो सीजन था जब कोहली अपने दमदार फॉर्म में थे और चार शतक टोक चुके थे। फाइनल में आकर उनके बल्ले से एक और शानदार पारी निकली। कोहली ने सनराइजर्स हैदराबाद के

खिलाफ 35 गेंदों पर 54 रन बनाए, लेकिन वह टीम को जीत नहीं दिला सके। पिछले साल खेले गए फाइनल में कोहली ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 35 गेंदों पर 43 रन बनाए।

कोहली का शानदार सीजन वैसे इस सीजन कोहली का फॉर्म देखा जाए तो उनके बल्ले से लगातार रन निकले हैं। अभी तक इस सीजन खेले 15 मैचों में कोहली के बल्ले से 600 रन निकले हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 164.38 और औसत 50 का रहा है।

इस सीजन कोहली ने चार अर्धशतक और एक शतक भी जमाया है। इस फॉर्म को देखते हुए कोहली से उम्मीद की जाएगी कि वह फाइनल में शानदार पारी खेलें और अपनी टीम को जीत दिलाते हुए दूसरा खिताब दिलाएं।



ऑपरेशन 'म्यूल हंट' के तहत साइबर ठगी नेटवर्क का भंडाफोड़, दो आरोपी गिरफ्तार

प्रथम न्यूज | चंडीगढ़

30 मई (पुनीत महाजन)

साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन म्यूल हंट के तहत साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, यूटी चंडीगढ़ ने एक संगठित साइबर ठगी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तारी साइबर धोखाधड़ी में इस्तेमाल किए जा रहे म्यूल बैंक खातों के दुरुपयोग से जुड़े एक मामले में की गई है।

यह कार्रवाई यूटी चंडीगढ़ की एस्पी (साइबर) गीतांजलि खंडेलवाल, आईपीएस के निर्देशों, डीएसपी साइबर क्राइम के

मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी साइबर क्राइम, सेक्टर-17 चंडीगढ़ की गिराणी में की गई।

पुलिस थाना साइबर क्राइम, चंडीगढ़ में एफआईआर नंबर 75 दिनांक 29.05.2026 भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 317(2), 49 एवं 61(2) के तहत दर्ज की गई है।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान

1. सलमान अंसारी (24 वर्ष), पुत्र सामिक अंसारी, निवासी गांव मिलाख, मुहलपुर, मोहाली (पंजाब)।
2. भीम सरोज (32 वर्ष), पुत्र राम किशुन, निवासी कृष्णा मंदिर के निकट, खुड्डु लाहौरा, चंडीगढ़।

जांच के दौरान भारतीय साइबर अपराध

समन्वय केंद्र (IyC), गृह मंत्रालय से प्राप्त सूचना के आधार पर पता चला कि चंडीगढ़ में संचालित कई बैंक खाते दिल्ली, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात सहित विभिन्न राज्यों में दर्ज साइबर धोखाधड़ी की शिकायतों से जुड़े हुए हैं। ये शिकायतें राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर दर्ज की गई थीं, जिनमें पीडिंटों ने ऑनलाइन ठगी के माध्यम से धन गंवाने की जानकारी दी थी।

बैंक खातों के गहन विश्लेषण से सामने आया कि इन खातों का उपयोग सामान्य बैंकिंग गतिविधियों के लिए नहीं किया जा रहा था, बल्कि इन्हें म्यूल अकाउंट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। ऐसे खातों का उपयोग साइबर अपराधी धोखाधड़ी से



प्राप्त धनराशि को छिपाने, ट्रांसफर करने और निकालने के लिए करते हैं।

जांच के दौरान कई संदिग्ध खातों की पहचान की गई और उनके खाताधारकों का सत्यापन किया गया। पृष्ठछाछ में आरोपी सलमान अंसारी और भीम सरोज ने अपने खातों में शामिल होने का बाद स्वीकार की। आरोपियों ने खुलासा किया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने सलमान अंसारी से म्यूल अकाउंट उपलब्ध कराने के लिए संपर्क किया था। इसके बाद सलमान ने भीम सरोज को नया बैंक खाता खुलवाने के लिए प्रेरित किया।

खाता खुलने के बाद उसकी जानकारी साइबर ठगी को उपलब्ध कराई गई। आरोपियों ने बताया कि खाते में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा

बड़ी रकम जमा कराई जाती थी, जिसे सलमान अंसारी बैंक के माध्यम से निकालकर ठगी तक पहुंचाता था। इसके बदले उन्हें कमीशन मिलता था, जिसे दोनों आपस में बांट लेते थे।

जांच में यह भी सामने आया कि चंडीगढ़ के ये बैंक खाते कई राज्यों में सक्रिय एक बड़े साइबर ठगी नेटवर्क का हिस्सा थे। आरोपियों की सिलसला उनके बैंक खातों में हुए वित्तीय लेन-देन और अन्य साक्ष्यों से प्रमाणित हुई है।

चंडीगढ़ पुलिस ने कहा कि साइबर अपराधियों और उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी तथा ऐसे नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है।

चंडीगढ़ सेक्टर 47 माउंट कार्मल स्कूल फीस बढ़ती मामला

आठ प्रतिशत से अधिक फीस वृद्धि अवैध करार



प्रथम न्यूज | चंडीगढ़

30 मई (पुनीत महाजन)

सेक्टर-47 स्थित माउंट कार्मल स्कूल द्वारा वर्ष 2017-18 में की गई फीस बढ़ोतरी के मामले में जिला अदालत ने 349 अभिभावकों के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्कूल प्रबंधन को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने स्कूल द्वारा की गई फीस वृद्धि को नियमों के विरुद्ध और अवैध करार देते हुए स्पष्ट किया कि कोई भी निजी स्कूल एक शैक्षणिक वर्ष

में 8 प्रतिशत से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकता। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि अधिक फीस जमाना करने की स्थिति में किसी भी छात्र का दाखिला रोकना या उसे किसी प्रकार से परेशान करना गैरकानूनी होगा। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि अभिभावक केवल 8 प्रतिशत तक बढ़ी हुई फीस देने के लिए ही बाध्य होंगे।

मामले की शुरुआत वर्ष 2017 में हुई थी, जब माउंट कार्मल स्कूल ने नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक की

ट्यूशन फीस में भारी बढ़ोतरी की घोषणा की थी। अभिभावकों के अनुसार करीब 2700 रुपये मासिक फीस को बढ़ाकर 4800 से 4975 रुपये तक कर दिया गया था।

इस फैसले का विरोध करते हुए अभिभावकों ने माउंट कार्मल पेरेंट्स एसोसिएशन का गठन किया और स्कूल प्रबंधन, चंडीगढ़ प्रशासन तथा सीबीएसई के समक्ष अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं। उचित कार्रवाई न होने पर 349 अभिभावकों ने जिला अदालत में सिविल केस दायर किया। सुनवाई

के दौरान स्कूल प्रबंधन ने अदालत में दलील दी कि वह एक गैर-सहायता प्राप्त निजी संस्थान है और फीस निर्धारण का अधिकार उसके पास है।

स्कूल ने यह भी कहा कि बढ़ोतरी का उद्देश्य बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं और बुनियादी ढांचे को बनाए रखना था। हालांकि अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और फीस वृद्धि को निर्धारित नियमों के विपरीत माना।

अभिभावकों ने अदालत को बताया कि फीस बढ़ोतरी से पहले पंजाब सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन दोनों ने निजी स्कूलों के लिए अधिकतम 8 प्रतिशत वार्षिक फीस वृद्धि की नीति लागू की थी। इसके बावजूद स्कूल ने मनमाने ढंग से फीस में भारी बढ़ोतरी कर दी।

अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि वर्ष 2017-18 से लेकर आगे भी अभिभावक केवल 8 प्रतिशत तक फीस बढ़ा सकते हैं और स्कूल प्रबंधन इससे अधिक राशि वसूल नहीं कर सकेगा। यह फैसला निजी स्कूलों में फीस वृद्धि के मामलों में अभिभावकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।

पंचकूला में दर्दनाक हादसा

ट्रक ने NHAI के तीन कर्मचारियों को कुचला, चालक गिरफ्तार

प्रथम न्यूज | पंचकूला

30 मई (पुनीत महाजन)

पंचकूला के मौली चौकी के समीप शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के तीन कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब सड़क पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के कर्मचारी सड़क पर नियमित रखरखाव और अन्य कार्यों में जुटे हुए थे। इसी दौरान तेज गति से आ रहे एक ट्रक ने नियंत्रण खो दिया और कर्मचारियों को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों कर्मचारी सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए।

घटना की सूचना मिलते ही एंबुलेंस और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। चिकित्सकों के अनुसार घायलों की हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है। पुलिस



ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रक चालक को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक जांच में हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। हादसे के कारण सड़क पर कुछ समय के लिए

यातायात बाधित रहा, जिसे बाद में पुलिस ने सुचारू रूप से बहाल कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने वाहन चालकों से सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्य वाले क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। साथ ही यातायात नियमों का पालन करने और निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने का संदेश दिया है।

